✷Website : www.kalamlok.com✷

वर्ष - 09 अंक - 332

बक्सर, गुरूवार 16 अप्रैल 2026

कलम लोक

पृष्ठ - 8
मूल्य 2 रू.

"सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। सत्य से उत्तम कुछ भी नहीं हैं और झूठ से बढ़कर तीव्रतर पाप इस जगत् में दूसरा नहीं है।

सीएम बनते ही एक्शन में सम्राट चौधरी, बोले- लापरवाही बर्दाश्त नहीं, तय समय में पूरा होगा काम

सीएम सम्राट चौधरी ने अपने पास रखे 29 विभाग, बाकी जिम्मेदारी विजय और बिजेंद्र में बांटी

पटना (कलम लोक)।

बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शपथ लेने के तुरंत बाद अपने कामकाज का तरीका साफ कर दिया. मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ ही समय बाद वह सीधे सचिवालय पहुंचे और वहां जाकर औपचारिक रूप से अपना कार्यभार संभाल लिया. इससे यह संकेत मिला कि वह शुरुआत से ही तेज रफ्तार में काम करना चाहते हैं.

बिहार में नई सरकार बनने के बाद मंत्रालयों का बंटवारा हो गया है. फिलहाल मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम के बीच ही सभी विभाग बांटे गए हैं. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने पास कुल 29 विभाग रखे हैं. इनमें कई अहम विभाग शामिल हैं, जैसे गृह, सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य, नगर विकास, कृषि और उद्योग. इसके अलावा उन्होंने वे विभाग भी अपने पास रखे हैं, जो पहले भाजपा और अन्य सहयोगी दलों के मंत्रियों के पास थे.

कार्यभार संभालने के बाद सम्राट चौधरी ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की. इस बैठक में कई विभागों के प्रधान सचिव और दूसरे बड़े अधिकारी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से साफ कहा कि विकास योजनाओं की रफ्तार बढ़ाई जाए और जो काम लंबे समय से रुके हुए हैं, उन्हें जल्द पूरा किया जाए.

बैठक में उन्होंने प्रशासनिक कामकाज को आसान और तेज बनाने पर भी जोर दिया. सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता जनता की समस्याओं का जल्दी समाधान करना है. लोगों को अपनी शिकायत लेकर बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी विभाग में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सभी विभाग तय समय सीमा के भीतर अपने लक्ष्य पूरे करें. उन्होंने साफ कहा कि जनता से जुड़े कामों में देरी नहीं होनी चाहिए. सम्राट चौधरी ने सड़क, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कानून-व्यवस्था को सबसे अहम क्षेत्र बताया. उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में तुरंत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यही आम लोगों के जीवन से सीधे जुड़े मुद्दे हैं.

सम्राट को इन विभागों की जिम्मेदारी

सम्राट चौधरी के पास जो विभाग हैं, उनमें गृह, राजस्व, स्वास्थ्य, उद्योग, पथ निर्माण, कृषि, आपदा प्रबंधन, पर्यटन, कला-संस्कृति, श्रम संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, खेल, पर्यावरण और पंचायती राज जैसे बड़े विभाग शामिल हैं. इसके अलावा वे सभी विभाग भी उनके पास हैं, जो अभी किसी अन्य मंत्री को नहीं दिए गए हैं.

नई सरकार ने संभाली कमान

मंगलवार को नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा. उसके बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई जिसमें सम्राट चौधरी को नेता चुना गया. उसके बाद सम्राट ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया. आज बुधवार को नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन लोक भवन में किया गया था. जिसमें सीएम और दो डिप्टी सीएम को राज्यपाल ने शपथ दिलाई.

अधिकारियों से क्या बोले सीएम?

सम्राट चौधरी ने अधिकारियों से कहा गया कि वे कामकाज में साफ-सफाई रखें और हर स्तर पर जवाबदेह रहें. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए ताकि सरकारी सेवाएं लोगों तक आसानी से पहुंच सकें. नई योजनाओं से जुड़े प्रस्तावों को भी तेजी से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया है. सम्राट चौधरी ने संकेत दिया कि उनकी सरकार बिहार के विकास को नई गति देने के लिए तेजी से फैसले लेने वाली है.

डिप्टी सीएम को मिली अहम जिम्मेदारी

जेडीयू के दोनों डिप्टी सीएम के बीच 18 विभागों का बंटवारा किया गया है. विजय चौधरी को 10 विभाग दिए गए हैं, जबकि बिजेंद्र यादव को 8 विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. दोनों नेताओं को जेडीयू कोटे के पुराने विभाग दिए गए हैं. सरकार की ओर से साफ किया गया है कि यह विभागों का बंटवारा अभी अस्थायी है. मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद नए मंत्रियों के बीच विभागों का अंतिम बंटवारा किया जाएगा. तब तक मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम ही पूरी जिम्मेदारी संभालेंगे.

11 देशों ने मिडल ईस्ट में तबाह हुए मुल्कों की मदद का किया ऐलान, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से क्या गुहार?

लंदन (एजेंसी)।

ब्रिटेन और जापान समेत 11 देशों के वित्त मंत्रियों ने ईरान जंग में तबाह हुए मध्य-पूर्व के मुल्कों की 'समन्वित' आर्थिक मदद की अपील की है। इन देशों ने बुधवार (15 अप्रैल) को विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से अपील की है कि प्रभावित देशों को 'समन्वित आपातकालीन सहायता' उपलब्ध कराई जाए, ताकि जरूरत के हिसाब से वित्तीय मदद और लचीले टूलकिट उपलब्ध कराए जा सकें। ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा, 'हम IMF और विश्व बैंक से अपील करते हैं कि वे ज़रूरतमंद देशों को समन्वित आपातकालीन सहायता प्रदान करें; यह सहायता उन देशों की परिस्थितियों के अनुरूप हो और इसमें उनके पास उपलब्ध सभी संसाधनों और लचीलेपन का पूरा इस्तेमाल किया जाए।'

बयान में आगे कहा गया है, 'अगर ईरान-अमेरिका के बीच शत्रुता फिर से शुरू हुई या संघर्ष का दायरा बढ़ा या होर्मुज़ समुद्री मार्ग में लगातार बाधाएं आती रहीं तो ये वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, उनकी सप्लाई चेन और दुनिया की आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए यह गंभीर अतिरिक्त जोखिम पैदा कर सकती हैं।'

इस बीच, रायटर्स ने ऊर्जा रिसर्च कंपनी Rystad Energy के डेटा का हवाला देते हुए बताया है कि मध्य-पूर्व युद्ध के कारण इस क्षेत्र को ऊर्जा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत पर 58 अरब डॉलर तक का खर्च उठाना पड़ सकता है; इसमें अकेले तेल और गैस सुविधाओं पर ही 50 अरब डॉलर तक का खर्च शामिल है। यह अनुमान रिसर्च फर्म के तीन हफ़्ते पहले के शुरुआती 25 अरब डॉलर के अनुमान से काफ़ी ज़्यादा है। यह 8 अप्रैल को US और ईरान के बीच हुए संघर्ष-विराम से पहले हुए नुकसान के व्यापक दायरे को दर्शाता है।

Rystad के सीनियर एनालिस्ट करण सतवानी कहते हैं, 'मरम्मत के काम से कोई नई क्षमता नहीं बनती। यह मौजूदा क्षमता को दूसरी तरफ़ मोड़ देता है, और इस बदलाव का असर प्रोजेक्ट में देरी और महंगाई के रूप में मध्य-पूर्व से कहीं दूर तक महसूस किया जाएगा।' उन्होंने कहा कि 58 अरब डॉलर का बिल तो सिर्फ़ मुख्य बात है, लेकिन वैश्विक स्तर पर ऊर्जा निवेश की समय-सीमा पर पड़ने वाले इसके दूरगामी प्रभाव भी उतने ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।'

मरम्मत में औसतन लगभग 46 अरब डॉलर खर्च की संभावना

Rystad का कहना है कि मरम्मत पर कुल खर्च औसतन लगभग 46 अरब डॉलर रहने की संभावना है; इसमें डाउनस्ट्रीम रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल संपत्तियों का हिस्सा सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वे काफ़ी जटिल होती हैं और उन्हें नुकसान भी बड़े पैमाने पर हुआ है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि औद्योगिक, बिजली और विलवणीकरण (desalination) संपत्तियों की मरम्मत पर अतिरिक्त 3 अरब से 8 अरब डॉलर तक का खर्च आ सकता है।

राघव चड्ढा को अब मिली जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा

नई दिल्ली (एजेंसी)। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को पंजाब सरकार द्वारा दी गई जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा वापस ले ली गई। इस खबर के सामने आने के कुछ ही देर बाद केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें सुरक्षा मुहैया करा दी गई। मौजूदा खतरे की आशंका के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा उन्हें जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। यह सुरक्षा दिल्ली और पंजाब, दोनों जगहों पर उपलब्ध होगी। उनकी सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि जब तक औपचारिकता पूरी नहीं कर ली जाती है, तब तक दिल्ली पुलिस को तत्काल सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने पिछले सप्ताह ही राघव चड्ढा का सुरक्षा घेरा हटा लिया था।

अनिल अंबानी पर ईडी ने और कसा शिकंजा

अमिताभ झुनझुनवाला और अमित बापना गिरफ्तार

मुंबई (एजेंसी)।

केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल अंबानी पर शिकंजा और कस दिया है। इसी सिलसिले में आडी ने रिलायंस समूह के दो पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों, अमिताभ झुनझुनवाला और अमित बापना, को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार, ये दोनों अनिल अंबानी के करीबी सहयोगी बताए जाते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने ये कार्रवाई रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड लोन धोखाधड़ी मामले में की है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ के बाद झुनझुनवाला को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि एजेंसी ने विस्तृत पूछताछ के लिए हिरासत में लिए जाने के अनुरोध को लेकर उन्हें अदालत के समक्ष पेश किया। यह जांच अनिल अंबानी समूह की कंपनियों जैसे रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) के माध्यम से फर्जी या मुखौटा कंपनियों का इस्तेमाल करके की गई कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से संबंधित है। झुनझुनवाला मार्च 2003 से सितंबर 2019 तक रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के निदेशक थे, जो आरएचएफएल और आरसीएफएल की होल्डिंग कंपनी है।

इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड) के खिलाफ एक नया आपराधिक मामला दर्ज किया था। इन पर LIC को कथित तौर पर 3,750 करोड़ रुपये का गलत नुकसान पहुंचाने का आरोप है।

सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को जमीन घोटाले में पेशी का आदेश

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हरियाणा के शिकोहपुर जमीन सौदे में कथित अनियमितताओं को लेकर दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा समेत सात अन्य आरोपियों को समन जारी किया है। आरोपियों को 16 मई को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। विशेष न्यायाधीश सुशांत चांगोत्रा ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए ये आदेश जारी किया है। इस संबंध में विस्तृत आदेश का इंतजार है। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति वाड्रा के खिलाफ पिछले साल जुलाई में चार्जशीट दाखिल की थी। यह पहली बार था जब किसी जांच एजेंसी ने 57 वर्षीय वाड्रा के खिलाफ किसी आपराधिक मामले में चार्जशीट दाखिल की थी।

पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली जमानत पर लगाई रोक

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ा झटका देते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्हें ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी गई थी। यह मामला असम पुलिस द्वारा खेड़ा के खिलाफ दर्ज मानहानि और जालसाजी से जुड़ा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की पत्नी रिनीकी भुइयां शर्मा ने पवन खेड़ा के खिलाफ असम पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी। खेड़ा ने आरोप लगाया था कि रिनीकी भुइयां के पास अलग-अलग देशों के कई पासपोर्ट हैं। इसी मामले में संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए खेड़ा ने तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां से उन्हें एक हफ्ते की राहत यानी ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिल गई थी।

जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने असम सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर पवन खेड़ा असम की किसी उचित अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के इस रोक वाले आदेश का उस अर्जी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। असम सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल (स्व) तुषार मेहता ने अदालत में कई अहम बातें रखीं। एसजी ने कहा कि पवन खेड़ा की याचिका में यह साफ नहीं है कि इस मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र कैसे बनता है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने भी इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि एफआईआर में दर्ज एक अपराध में अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है।

कांग्रेस की ना-नुकुर के बीच प्रतिभा पाटिल का महिला आरक्षण को समर्थन, पीएम को लिखा पत्र

नई दिल्ली (एजेंसी)। महिला आरक्षण कानून यानी 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के ऐतिहासिक कदम को देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का मजबूत और खुला समर्थन मिला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर इस पहल की जमकर सराहना की है। राजनीतिक दृष्टिकोण से यह पत्र बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल प्रतिभा पाटिल का यह समर्थन ऐसे समय में आया है, जब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस कानून की समय-सीमा और अन्य तकनीकी पहलुओं जैसे परिसीमन और कोटा को लेकर लगातार ना-नुकुर कर रही है। 11 अप्रैल को पुणे स्थित अपने आवास 'रायगढ़' से लिखे गए इस पत्र में पूर्व राष्ट्रपति ने इस कानून को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक 'परिवर्तनकारी कदम' करार दिया है।

ब्रिक्स सम्मेलन के लिए भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन, सालभर में होगी दूसरी यात्रा

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत में इस साल के आखिरी में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल होंगे। रूसी समाचार एजेंसी TASS ने बुधवार को क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के हवाले से यह जानकारी दी। हालांकि, अभी तक इस शिखर सम्मेलन के लिए कोई आधिकारिक तारीखें तय नहीं हुई हैं, लेकिन एक सूत्र के हवाले से बताया गया था कि यह 12-13 सितंबर को हो सकता है। ऐसे में पुतिन भारत आते हैं तो सालभर में उनकी दूसरी भारत यात्रा होगी।

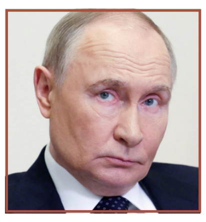

रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने आखिरी बार दिसंबर 2025 में भारत का दौरा किया था। तब उन्होंने 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी के साथ बातचीत की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना था। BRICS की आने वाली बैठक, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के बीच बने इस अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की 18वीं बैठक होगी। इन देशों के अलावा, कुछ और देश भी हैं जो पर्यवेक्षक और नए सदस्यों के तौर पर इस अंतर्राष्ट्रीय समूह का हिस्सा हैं।

इससे पहले, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4-5 दिसंबर, 2025 को 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत के नई दिल्ली आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वागत किए जाने के बाद, इस यात्रा ने वैश्विक दबावों के बावजूद आर्थिक संबंधों, ऊर्जा सहयोग और रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की।

लखनऊ में भीषण आग, 1000 से अधिक झोपड़ियां जलीं, विस्फोटों से दहला इलाका

लखनऊ (एजेंसी)। लखनऊ के विकासनगर थाना क्षेत्र में भीषण आग लग गई है। विकासनगर में विनायकपुरम झुग्गी बस्ती में बुधवार शाम करीब चार बजे आग लग गई। देखते-देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। गैस सिलेंडर और बस्ती में खड़ी बाइकों के फ्यूल टैंक में ताबड़तोड़ विस्फोट होने से इलाका दहल गया। आग पूरी बस्ती में फैल गई। अग्निकांड में करीब 1000 से अधिक झुग्गी बस्ती जल गई भगदड़ मच गई। कई लोगों के बच्चे फंस गए। वह चीख-पुकार कर रहे थे। इस बीच पहुंची पुलिस और दमकल कर्मियों ने लोगों को बाहर निकाला तो वह बच्चों के फंसे होने का हवाला देकर भिड़ गए। कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। पथराव में सिविल डिफेंस के पोस्ट वार्डन ऋषि श्रीवास्तव का सिर फट गया। कई अन्य लोग घायल हो गए।

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पुलिस महानिदेशक अग्निशमन सुजीत पांडेय, पुलिस कमिश्नर अमरेन्द्र कुमार सेंगर और डीएम विशाख जी पहुंचे। उन्होंने लोगों को समझाकर शांत कराकर। कुछ दूर पर स्थित मिनी स्टेडियम में भेज दिया। अग्निकांड में करीब 1000 से अधिक झुग्गी बस्ती जल गई। देर रात तक दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में लगे रहे। बस्ती में रहने वाले विशाल गौतम इटौंजा के कुंवरपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि बस्ती में अधिकतर लोग सीतापुर के महमूदाबाद, लखीमपुरखीरी, बहराइच और पड़ोसी जनपदों के रहने वाले हैं। वह करीब 25-30 साल से यहां रह रहे हैं। शाम करीब चार बजे देशी शराब ठेके के बगल में बनी कैंटीन से आग की एकाएक लपटें उठीं और विकराल रूप धारण कर लिया।

पुलिस ने रोका तो भीड़ उग्र हो गई

रहमान ने बताया कि उनके चार बच्चे अंदर ही फंसे हैं। वहीं, एक महिला ने कहा कि उसके दो बच्चे फंसे हैं। लोग अंदर जाने की जिद कर रहे थे। पुलिस ने रोका तो लोग उग्र हो गए। उन्होंने पथराव कर दिया। पथराव में बस्ती के लोगों के साथ ही पुलिस और सिविल डिफेंस के कर्मी समेत आठ से 10 लोग घायल हो गए। देर रात तक दमकल कर्मी आग पर काबू पाते रहें। लोगों ने बताया कि 1000 से अधिक झोपड़ियां बस्ती में थी। उनकी गृहस्थी उसमें रखा सामान, नकदी सब जल गई। कई लोगों के तो बच्चों की शादी थी। उनका दहेज और शादी का अन्य सामान सब जल गया। लोगों ने बताया कि उनके यहां पले मुर्गे, बकरियां, कुत्ते समेत करीब 50 मवेशी जल गए। कई लोग गृहस्थी निकालने में झुलस भी गए।

बीजेपी का गेमचेंजर मूव, सम्राट चौधरी के साथ बिहार में नए युग की शुरुआत

पटना (संवाददाता)। कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर में नहीं, इतिहास में दर्ज होती हैं. 14 अप्रैल 2025 बिहार की राजनीति के लिए वैसी ही तारीख है. जिस दिन देश अपने संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर को नमन कर रहा था, उसी दिन बिहार की सत्ता की चाबी उन हाथों में पहुँची जिनकी कल्पना पांच दशक पहले शायद किसी ने नहीं की होगी. नीतीश कुमार का इस्तीफा, सम्राट चौधरी का NDA विधायक दल का नेता चुना जाना यह सब एक दिन में हुआ जरूर, लेकिन इसकी नींव दशकों पहले रखी गई थी.

बिहार में बीजेपी की राजनीतिक यात्रा किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है बस फ़र्क यह है कि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं था. 1980 के दशक मेंपार्टी की शुरुआत मात्र 21 सीटों से हुई. कैलाशपति मिश्र जैसे नेता पहचान के लिए जूझ रहे थे. 1985 में हालात और बिगड़े, उस दौर में बिहार की राजनीति पर कुछ चुनिंदा चेहरों का एकाधिकार था और बीजेपी हाशिये पर खड़ी एक उम्मीद भर थी. लेकिन 1990 के दशक में नए सामाजिक समीकरण बने, मंडल-कमंडल की राजनीति ने पूरे देश का परिदृश्य बदला. बीजेपी ने इस दौर में धीरे-धीरे अपनी जमीन तैयार की. ना हड़बड़ी में, न शोरगुल में, बल्कि संगठन की ताकत से धीरे-धीरे अपना विस्तार किया. 2000 के बाद सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार के गठबंधन ने बीजेपी को एक नई रफ़्तार दी. 2010 में 91 सीटें लाना बीजेपी के लिए यह एक ज़बरदस्त छलांग थी. फिर 2020 में 74 और 2025 में 89 सीटें लाकर बीजेपी ने सभी को चौंका दिया. जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को बिहार में मुख्यमंत्री पद मिल गया, वो गलत कहते हैं. यह मिला नहीं यह कमाया गया है. सीट दर सीट, बूथ दर बूथ, दशक दर दशक.

काम से बनी पहचान

सम्राट चौधरी के नेतृत्व की सबसे बड़ी पहचान यही मानी जा रही है कि फैसले सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि जमीन पर असर दिखाते हैं. यही वजह है कि उनके हालिया कदमों को घोषणाओं की राजनीति से आगे बढ़कर 'परफॉर्मेंस की राजनीति' के तौर पर देखा जा रहा है. 2024-25 का 2.79 लाख करोड़ का बजट बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है. लेकिन यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, यह उस महत्वाकांक्षा का संकेत है, जिसमें राज्य खुद को तेज विकास की राह पर ले जाना चाहता है. इसके साथ ही 30,547 सरकारी पदों का सृजन, बेरोजगारी जैसी पुरानी समस्या पर सीधा और ठोस प्रहार माना जा रहा है.

दशकों से OBC वोटबैंक पर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का दबदबा रहा है. यह वोटबैंक बिहार की राजनीति की रीढ़ है. सम्राट चौधरी को आगे लाकर बीजेपी ने इस स्पेस में सिर्फ दस्तक नहीं दी बल्कि दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई है. अब विपक्ष के लिए बीजेपी OBC विरोधी है वाला तर्क चलाना इतना आसान नहीं रहेगा. मुंगेर और उसके आसपास का इलाका पारंपरिक रूप से विपक्ष का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है. वहीं से बीजेपी का मुख्यमंत्री आना यह सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से विपक्ष के लिए विनाशकारी है. संदेश साफ है कि बीजेपी अब सिर्फ मौजूदगी नहीं, प्रभुत्व की राजनीति कर रही है. राजनीति में क्लीन इमेज कहना आसान है, निभाना बेहद मुश्किल. सम्राट चौधरी ने वित्त मंत्री से लेकर गृह मंत्री तक हर पद पर बिना किसी गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप के काम किया है. बिहार जैसे राज्य में, जहाँ राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप रोज का खेल है, यह अपने आप में एक उपलब्धि है.

गृह मंत्रालय में भी उनकी कार्यशैली साफ तौर पर दिखी है. अपराधियों पर बिना भेदभाव सख्त कार्रवाई, महिला सुरक्षा के लिए अभय ब्रिगेड और पिंक पॉलिसिंग जैसे कदम और न्याय व्यवस्था को तेज करने के लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना. न्याय में देरी ही अन्याय है- इस सोच को नीति में बदलने की कोशिश साफ नजर आती है. साथ ही, हर थाने में जनता दरबार की पहल पुलिस को अधिक जवाबदेह बनाने की दिशा में एक अहम कदम है. पुलिसकर्मियों के परिवारों के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना यह दिखाती है कि सिस्टम को मजबूत करने के साथ-साथ उससे जुड़े लोगों का भी ख्याल रखा जा रहा है. करीब 46 साल की राजनीतिक यात्रा के बाद भारतीय जनता पार्टी का बिहार में अपना मुख्यमंत्री होना सिर्फ एक पार्टी की उपलब्धि नहीं, बल्कि राज्य की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है. सम्राट चौधरी के नेतृत्व में कुछ बातें स्पष्ट दिखती हैं- डबल इंजन सरकार को अब वास्तविक गति मिल सकती है, जहां केंद्र और राज्य के बीच तालमेल और मजबूत होगा. सामाजिक संतुलन को लेकर भी संदेश साफ है कि OBC, EBC और दलित समुदायों को प्रतिनिधित्व और भागीदारी का भरोसा दिया जा रहा है.

सम्राट चौधरी के जरिए रणनीतिक संदेश

बिहार में बीजेपी पर लंबे समय से एक ठप्पा लगाने की कोशिश होती रही कि ये सवर्णों की पार्टी है. विपक्ष ने इस नैरेटिव को बड़ी मेहनत से गढ़ा और चुनाव दर चुनाव इस्तेमाल किया. लेकिन सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने वह काम कर दिखाया जो विपक्ष को कभी उम्मीद नहीं थी उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के मैदान में, जवाब दे दिया. सम्राट चौधरी कोइरी-कुशवाहा समुदाय से आते हैं. 16 नवंबर 1968 को मुंगेर ज़िले के लखनपुर गाँव में जन्मे सम्राट चौधरी की राजनीतिक विरासत भी उतनी ही मज़बूत है. पिता शकुनी चौधरी सात बार सांसद/विधायक रहे, माँ पार्वती देवी भी विधायक रहीं. लेकिन इन्हें सिर्फ विरासत का नेता कहना अन्याय होगा. 1990 से सक्रिय राजनीति में तीन दशकों से अधिक का अनुभव, वित्त, गृह, खेल, पंचायती राज जैसे अहम मंत्रालय, उपमुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का पद. यह ट्रैक रिकॉर्ड किसी परिचय का मोहताज नहीं.

सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही पीएम मोदी ने दी बधाई

बिहार में नई सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है. बुधवार को सम्राट चौधरी ने बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. उनके साथ जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली.

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सम्राट चौधरी के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके पास ऊर्जा, जनसेवा का जज्बा और जमीन से जुड़ा अनुभव है. पीएम ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार जनता की उम्मीदों को पूरा करेगा और विकास के नए मुकाम हासिल करेगा. पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा कि सम्राट चौधरी का नेतृत्व राज्य के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा. उन्होंने भरोसा जताया कि बिहार चौतरफा विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा और लोगों की आकांक्षाएं पूरी होंगी.

प्रधानमंत्री ने दोनों नए डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र यादव को भी बधाई दी. उन्होंने कहा कि इन दोनों नेताओं का लंबा राजनीतिक अनुभव और जनहित के प्रति समर्पण बिहार के विकास को नई रफ्तार देगा. पीएम ने यह भी कहा कि इनके काम से राज्य में सुशासन, पारदर्शिता और जनकल्याण के नए मानक स्थापित होंगे. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन ने भी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनने पर शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सम्राट चौधरी 'विकसित भारत, विकसित बिहार' के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे. उन्होंने सम्राट चौधरी के सफल कार्यकाल की कामना की.

'सुशासन बाबू' अब बने पूर्व मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार ने बदला बायो, सम्राट चौधरी के लिए क्या लिखा?

पटना (संवाददाता)। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है. लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार अब पूर्व मुख्यमंत्री बन गए हैं. उन्होंने सम्राट चौधरी को बधाई देते हुए नई सरकार के लिए भरोसा जताया है. सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर अपना बायो बदल लिया है. अब उन्होंने खुद को पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद और जदयू अध्यक्ष के रूप में दर्ज किया है. यह बदलाव बिहार की राजनीति में नए दौर की शुरुआत का संकेत माना जा रहा है.

नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार और तेजी से विकास करेगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य जल्द ही देश के सबसे विकसित राज्यों में शामिल होगा. सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार काफी एक्टिव नजर आए. उन्होंने सभी नेताओं से गर्मजोशी से मुलाकात की. बताया जा रहा है कि वे मुख्यमंत्री आवास छोड़ने की तैयारी भी कर चुके हैं और जल्द नए आवास में शिफ्ट हो सकते हैं.

बहार में पहली बार भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनी है. सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने में नीतीश कुमार की अहम भूमिका रही. उनके प्रस्ताव पर ही एनडीए विधायकों ने सम्राट के नाम को मंजूरी दी. नई सरकार में जदयू के विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव को उपमुख्यमंत्री बनाया गया है. फिलहाल मुख्यमंत्री और दो डिप्टी सीएम ही सरकार चला रहे हैं. कैबिनेट विस्तार विधानसभा में बहुमत साबित होने और अन्य राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद किया जाएगा.

एनडीए बैठक में हुआ फैसला

एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार ने ही सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा. इस प्रस्ताव को गठबंधन के सभी विधायकों ने समर्थन दिया. इस दौरान नीतीश कुमार ने खुद सम्राट चौधरी को माला पहनाकर स्वागत किया.

पुराने रिश्तों की झलक भी दिखी

नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के परिवार का पुराना राजनीतिक रिश्ता रहा है. समता पार्टी के दौर में सम्राट के पिता शकुनी चौधरी भी नीतीश के साथ थे. दोनों ने मिलकर लालू यादव के खिलाफ 'लव-कुश' का समीकरण बनाया था.

शपथ के बाद काम में जुटे सम्राट चौधरी

शपथ लेने के तुरंत बाद सम्राट चौधरी एक्टिव हो गए. उन्होंने सचिवालय जाकर पदभार संभाला और अधिकारियों के साथ बैठक की. इसके बाद भाजपा कार्यालय में उनका भव्य स्वागत हुआ, जहां समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी की.

सम्राट के सीएम बनने पर भावुक हुए पिता शकुनी चौधरी

बोले- जो मैं नहीं कर सका, बेटे ने कर दिखाया

पटना (संवाददाता)। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर उनके पिता और वरिष्ठ नेता शकुनी चौधरी काफी भावुक नजर आए. उन्होंने कहा कि यह उनके परिवार के लिए गौरव का क्षण है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो मुकाम वह खुद नहीं हासिल कर सके, वह उनके बेटे ने हासिल कर लिया.

शकुनी चौधरी ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन को याद करते हुए कहा कि उन्होंने कई सालों तक संघर्ष किया. उन्होंने लव-कुश समीकरण को मजबूत करने में भूमिका निभाई और समता पार्टी व हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जैसे दलों के निर्माण में भी योगदान दिया. इसके बावजूद वह मुख्यमंत्री पद तक नहीं पहुंच सके. उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी का इस पद तक पहुंचना उनके लिए एक सपने के पूरा होने जैसा है. शकुनी चौधरी ने कहा कि यह सफलता केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि बड़े नेताओं के भरोसे का परिणाम है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार के समर्थन को इसका बड़ा कारण बताया. उनके मुताबिक, किसी भी नेता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी तभी मिलती है, जब उसमें खास क्षमता और नेतृत्व की ताकत हो.उन्होंने यह भी कहा कि जब भाजपा और जदयू जैसे अलग-अलग राजनीतिक विचारधारा वाले दल एक नाम पर सहमत होते हैं, तो यह उस नेता की स्वीकार्यता को दिखाता है. सम्राट चौधरी ने न सिर्फ अपनी पार्टी, बल्कि गठबंधन के सभी नेताओं और जनता का भरोसा जीता है, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है. शकुनी चौधरी ने यह भी कहा कि जब किसी युवा नेता को देश के प्रधानमंत्री और राज्य के वरिष्ठ नेताओं का समर्थन मिलता है, तो उससे बड़ी उम्मीदें भी जुड़ जाती हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि सम्राट चौधरी इन उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे.

2014 में जीता भरोसा, 2026 में मिला ताज

सम्राट कैसे बने नीतीश के भरोसेमंद?

पटना (संवाददाता)। बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बनने वाले सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. उनके मुख्यमंत्री बनने में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन सबसे अहम माना जा रहा है. यह भरोसा अचानक नहीं बना, बल्कि कई सालों की राजनीति और रिश्तों का नतीजा है. सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी बिहार के पुराने और मजबूत नेताओं में गिने जाते हैं. जब नीतीश कुमार ने समता पार्टी बनाई थी, तब शकुनी चौधरी उनके करीबी साथियों में थे. दोनों नेताओं के बीच लंबे समय से राजनीतिक संबंध रहे हैं. इसी पुराने रिश्ते ने भी सम्राट के लिए रास्ता आसान किया.

सम्राट चौधरी कभी नीतीश कुमार के विरोध में खुलकर बयान दे चुके थे. उन्होंने एक समय कहा था कि नीतीश को हटाए बिना मुरेठा नहीं खोलेंगे. लेकिन समय के साथ राजनीति बदली और दोनों के बीच भरोसा मजबूत हुआ. यह भरोसा 2024 में डिप्टी सीएम बनने के बाद नहीं, बल्कि 2014 में ही बन गया था. 2014 में जब नीतीश कुमार भाजपा से अलग होकर अकेले पड़ गए थे, तब सम्राट चौधरी ने बड़ा राजनीतिक कदम उठाया था. उन्होंने लालू यादव की पार्टी राजद में टूट कराई और कई विधायकों को अलग कर दिया. उस समय यह कदम नीतीश कुमार के लिए राहत लेकर आया. इसी दौर में सम्राट, नीतीश के साथ हेलिकॉप्टर से अपनी विधानसभा परबत्ता भी गए थे. 2014 में उन्होंने राजद छोड़ा और पिता के साथ जदयू में शामिल हो गए. फिर 2015 में जब नीतीश और लालू साथ आए, तो सम्राट जीतनराम मांझी की पार्टी हम में चले गए. वहां चुनाव में हार मिली. कुछ समय बाद उन्होंने भाजपा का दामन थामा. दिलचस्प बात यह रही कि कभी उनके विरोधी रहे सुशील मोदी ही उन्हें भाजपा में लेकर आए. 2017 में भाजपा में शामिल होने के बाद सम्राट चौधरी की राजनीति ने तेजी पकड़ी. पार्टी ने उन्हें ओबीसी चेहरे के रूप में आगे बढ़ाया. पहले प्रदेश उपाध्यक्ष, फिर विधान परिषद सदस्य और बाद में पंचायती राज मंत्री बनाया गया.

2022 में भाजपा ने उन्हें विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया. उनके आक्रामक अंदाज ने पार्टी नेतृत्व को प्रभावित किया. इसके बाद उन्हें बिहार भाजपा अध्यक्ष बनाया गया. 2024 में नीतीश कुमार जब फिर एनडीए में लौटे, तब सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया.अब करीब दो साल के भीतर सम्राट चौधरी ने डिप्टी सीएम से मुख्यमंत्री तक का सफर तय कर लिया है. उनकी यह सफलता राजनीतिक धैर्य, रणनीति और सही समय पर सही फैसलों का परिणाम मानी जा रही है. बिहार की राजनीति में यह एक नए दौर की शुरुआत मानी जा रही है.

करियर की शुरुआत राजद से की

57 वर्षीय सम्राट चौधरी का राजनीतिक जीवन कई दलों से होकर गुजरा है. उन्होंने शुरुआत राजद से की थी. राबड़ी देवी सरकार में वह मंत्री भी बने, लेकिन उम्र विवाद के कारण पद छोड़ना पड़ा. बाद में वह दो बार राजद के टिकट पर विधायक बने.

समाज में न्याय और समानता की प्रेरणा देता रहेगा बाबा साहेब का जीवन : मुख्यमंत्री

समाज में न्याय और समानता की प्रेरणा देता रहेगा बाबा साहेब का जीवन, रायपुर में डॉ. भीमराव अंबेडकर की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का भव्य अनावरण

रायपुर।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर के सामने स्थित डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर चौक में उनकी 21 फीट ऊंची पंचधातु से निर्मित भव्य प्रतिमा का अनावरण किया।

इस अवसर पर आयोजित गरिमामय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बाबा साहेब का जीवन संघर्ष, शिक्षा और समानता की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के नेतृत्व और उनके द्वारा निर्मित भारतीय संविधान ने वंचित, शोषित और पिछड़े वर्गों को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाया है। उनके विचार आज भी समाज को न्याय और समानता की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं। मुख्यमंत्री ने आयोजन समिति की मांग पर मंगल भवन, सामुदायिक भवन सहित विभिन्न निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्यों के लिए 60 लाख रुपये की राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह राशि स्थानीय स्तर पर सामाजिक गतिविधियों और जनसुविधाओं को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारतीय संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार प्रदान किया है। इसी कारण आज समाज के सभी वर्गों को अपने जीवन में आगे बढ़ने के समान अवसर प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर बल देते हुए कहा कि बाबा साहेब ने विपरीत परिस्थितियों में भी कोलंबिया विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त कर यह सिद्ध किया कि शिक्षा ही समाज परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम है। उन्होंने कहा कि आज देश के प्रत्येक कोने में बाबा साहेब की प्रतिमाएं स्थापित हैं, जो उनके प्रति लोगों के अटूट सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक हैं। रायपुर सहित पूरे प्रदेश में उनकी जयंती हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है, जिससे नई पीढ़ी निरंतर प्रेरणा प्राप्त कर रही है। मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण पर बाबा साहेब के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी भी समाज की प्रगति वहां की महिलाओं की स्थिति से आंकी जाती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार बाबा साहेब के सपनों को साकार करने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना और जल जीवन मिशन जैसी योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का माध्यम बन रही हैं। उन्होंने कहा कि 'विकसित भारत' के लक्ष्य के साथ छत्तीसगढ़ सरकार भी 'विकसित छत्तीसगढ़' के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है, जिसमें बाबा साहेब के आदर्श मार्गदर्शक हैं। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने नागरिकों से आह्वान किया कि वे बाबा साहेब के विचारों को आत्मसात करते हुए सामाजिक समरसता, समानता और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। इस अवसर पर कौशल विकास मंत्री श्री खुशवंत साहेब, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक श्री किरण सिंह देव, महापौर नगर पालिक निगम रायपुर श्रीमती मीनल चौबे, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, श्री अनुज शर्मा, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री अमरजीत सिंह छाबड़ा, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया नमन

सामाजिक न्याय, समानता और समरस समाज के निर्माण का लिया संकल्प

रायपुर।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में भारतरत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव, विधायक श्री रोहित साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री साय ने बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन वंचित, शोषित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा एवं उनके उत्थान के लिए समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहब का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हम समाज में समरसता, न्याय और समानता के मूल्यों को सशक्त करें और अंतिम व्यक्ति तक विकास के लाभ सुनिश्चित करें।उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे डॉ. अम्बेडकर के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करें तथा एक न्यायपूर्ण, समरस और सशक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं।

संविधान हमारे लोकतंत्र की आत्मा है और समरसता उसकी सबसे बड़ी शक्ति : मुख्यमंत्री

संविधान के मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प: समरसता भोज में शामिल हुए मुख्यमंत्री साय

रायपुर।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर के शंकरनगर स्थित दुर्गा मैदान में डॉ. भीमराव आंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर आयोजित समरसता भोज कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और आमजन के साथ बैठकर भोजन किया तथा स्वयं लोगों को भोजन परोसकर सामाजिक समरसता का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसके संविधान का निर्माण करने का गौरव बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर को प्राप्त है। उन्होंने कहा कि यह संविधान देश के 140 करोड़ नागरिकों को समानता, अधिकार और गरिमा के साथ जीवन जीने का आधार प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने दृढ़ संकल्प और अदम्य इच्छाशक्ति के बल पर उच्चतम स्थान प्राप्त किया और समाज के वंचित, शोषित एवं कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने नारी शिक्षा और सम्मान के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले द्वारा प्रारंभ किए गए नारी शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के अभियान को बाबा साहेब ने आगे बढ़ाया और उसे नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बाबा साहेब के जन्म, शिक्षा, दीक्षा, कार्य और समाधि स्थलों को 'पंच तीर्थ' के रूप में विकसित कर उन्हें सच्चा और स्थायी सम्मान दिया जा रहा है।

इस अवसर पर मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि बाबा साहेब का जीवन संघर्ष, शिक्षा और समरसता का प्रेरक उदाहरण है। उनके विचार आज भी समाज को समानता और न्याय की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। समरसता भोज जैसे आयोजन सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक श्री किरण सिंह देव ने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान के माध्यम से समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने की मजबूत व्यवस्था दी। आज मुख्यमंत्री श्री साय और के नेतृत्व में अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। समरसता भोज कार्यक्रम में विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री अमरजीत सिंह छाबड़ा, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष श्रीमती मोना सेन सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

नवा रायपुर में जनसैलाब के बीच गरिमामय वातावरण में मनाई गई डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती

अंबेडकर चौक में बाबा साहब की आदमकद कांस्य प्रतिमा का होगा अनावरण

रायपुर।

भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर नवा रायपुर अटल नगर स्थित इंद्रावती भवन के समीप कैपिटल कॉम्प्लेक्स क्षेत्र के अंबेडकर चौक में एक भव्य एवं गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डां बी.आर. अंबेडकर जयंती समारोह, संयुक्त आयोजन समिति के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ताओं, युवाओं एवं आम नागरिकों की बड़ी संख्या में सहभागिता रही। सुबह से ही अंबेडकर चौक पर लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा और पूरे क्षेत्र में 'जय भीम' एवं संविधान के जयघोष गूंजते रहे।

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री गुरु खुशवंत साहेब मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, एवं अध्यक्षता महादेव कांवरे, संभागायुक्त रायपुर द्वारा की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके पश्चात संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन कर उपस्थित जनों को संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई गई। अंबेडकर चौक से एक भव्य रैली भी

निकाली गई, जिसमें नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए सामाजिक समानता और न्याय के संदेश को जन-जन तक पहुंचाया। समारोह के दौरान आयोजन समिति द्वारा अंबेडकर चौक में संविधान निर्माता डॉ. अंबेडकर की आदमकद कांस्य प्रतिमा स्थापित करने की मांग रखी गई। इस पर मुख्य अतिथि मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में यहां एक भव्य एवं विशाल प्रतिमा अवश्य स्थापित की जाएगी। मंत्री जी का यह व्यक्त्तव उपस्थित जनसमूह के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रही। मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने अपने विस्तृत उद्बोधन में कहा कि डॉ. अंबेडकर का जीवन संघर्ष, शिक्षा और आत्मसम्मान की एक प्रेरणादायक गाथा है। उन्होंने बताया कि बाबासाहेब ने अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त की और अपने ज्ञान, परिश्रम एवं दूरदर्शिता के बल पर भारत को विश्व का सबसे मजबूत संविधान प्रदान किया। उन्होंने कहा कि डॉ. अंबेडकर ने अपना संपूर्ण जीवन समाज के वंचित, शोषित एवं पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित किया, जो आज भी हम सभी के लिए मार्गदर्शक है। अपने वक्तव्य में मंत्री ने समाज को एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि डॉ. अंबेडकर के विचार केवल किसी एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव समाज के लिए प्रेरणास्त्रोत हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें उनके बताए मार्ग पर चलते हुए शिक्षा, समानता और अधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना होगा। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे अपने अधिकारों को जानें, समझें और संविधान के मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएं, ताकि एक समरस, समान और सशक्त समाज का निर्माण किया जा सके।

कार्यक्रम में विभिन्न वक्ताओं ने डॉ. अंबेडकर के जीवन, उनके विचारों और समाज में लाए गए क्रांतिकारी परिवर्तनों पर विस्तार से प्रकाश डाला। दिलीप वासनिकर ने संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों की जानकारी देते हुए इसे विश्व का सबसे प्रभावशाली दस्तावेज बताया, वहीं कमल वर्मा ने कर्मचारियों और आम नागरिकों को अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। धनंजय देवांगन ने सामाजिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता को संविधान की मूल भावना बताते हुए कहा कि यह सभी वर्गों के समग्र विकास का आधार है। सुभाष मिश्रा, अनिल बनज एवं आलोक देव ने जातिविहीन समाज की स्थापना, सामाजिक समता जैसे विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। मंजू बंसोड़ ने महिला सशक्तिकरण में डॉ. अंबेडकर के योगदान को रेखांकित किया, जबकि डॉ आर. के. सुखदेवे ने शिक्षा को समाज के विकास की आधारशिला बताया। आर. पी. भतपहरी ने वंचित एवं कमजोर वर्गों के उत्थान में डॉ. अंबेडकर की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि डॉ. अंबेडकर केवल एक महान नेता ही नहीं, बल्कि एक विचारधारा हैं, जिनकी प्रासंगिकता आज भी समाज में बनी हुई है। संयुक्त आयोजन समिति के संयोजक देवलाल भारती ने अपने संबोधन में कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों को डॉ. अंबेडकर के विचारों से जोड़ना तथा असमानता को दूर कर समानता की भावना को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज को जागरूक करने और संविधानिक मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर उपस्थित सभी आमंत्रितों एवं नागरिकों को डॉ. अंबेडकर का पैरा आर्ट फोटोफ्रेम संविधान की प्रस्तावना तथा संविधान की पुस्तकें भेंट की गईं। कार्यक्रम में अश्विनी कुमार बंजारा, एच.के. रंगारी, अगर लाल जोशी, कमलेश बंसोड, राजीव अहिरे कृष्ण लाल कश्यप, विमल शाण्डिल्य, शैलेंश टेंबुरने, कैलाश नेताम, घनश्याम साहू, यू एस राठिया, भूपेन्द्र सिंह ठाकुर, एन आर चंद्रवंशी, एल. एन. कोसरिया , श्रीमती विद्या भारती, सुश्री कांति सूर्यवंशी, आशा पात्रे, टीकू रावटे, उमेश सिंह, अनिल मालेकर, अश्विन पात्रे, ए.एस. मरावी, जी.एस. पैकरा, डी.एस. धुवे, राजदेव लकड़ा, वीरेंद्र मिरचे, रमेश घिदौडे, मुक्त नंद खूंटे, एस.आर. टंडन सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक स्थानीय, मंडल अध्यक्ष श्री देशवन बघेल ग्रामीण सरपंच, उप सरपंच, जनपद प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। समारोह के अंत में उपस्थित सभी लोगों ने डॉ. अंबेडकर के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने तथा संविधान के मूल्यों का पालन करने का संकल्प लिया। यह आयोजन न केवल डॉ. अंबेडकर के प्रति श्रद्धा का प्रतीक रहा, बल्कि समाज में समानता, न्याय और बंधुत्व के संदेश को सशक्त रूप से प्रसारित करने में भी सफल रहा।

विकसित भारत के लिए, प्रगति, प्रकृति और संस्कृति की त्रिवेणी जरूरी : पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने देहरादून में आयोजित भव्य समारोह में किया 210 किमी लंबे, दिल्ली -देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का लोकार्पण

देहरादून (एजेंसी)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जसवंत सिंह आर्मी ग्राउंड, गढ़ी कैंट में आयोजित समारोह में 210 किमी लंबे, दिल्ली -देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का रिमोट बटन दबाकर लोकार्पण किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गढ़ी कैंट तक 12 किलोमीटर लंबे रोड शो में प्रतिभाग करने के साथ ही डाटकाली मंदिर में दर्शन करने के उपरांत पूजा भी की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गढ़ी कैंट में आयोजित, समारोह में अपने संबोधन की शुरुआत देशवासियों को बैसाखी और बिहू पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आने वाले कुछ दिनों में उत्तराखंड में स्थित पवित्र चार धामों की भी यात्रा शुरु होने वाली है, जिसका देशभर के आस्थावान लोग प्रतीक्षा करते हैं। दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने से चारधाम के यात्रियों को भी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य अपने स्थापना के 26वें प्रवेश कर चुका है, अब राज्य की प्रगति में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस-वे भी शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ साल पहले उन्होंने बाबा केदार की धरती पर अनायास ही कहा था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड के नाम होने जा रहा है, उन्हें यह देखकर बेहद खुशी हो रही है कि डबल इंजन वाली सरकार की नीतियों और उत्तराखंड के लोगों के परिश्रम से उत्तराखंड तेजी से इस राह पर बढ़ रहा है।

प्रधानमंत्री ने संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ बीआर अंबेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि बीते एक दशक से उनकी सरकार ने जो भी निर्णय लिए वो देश के संविधान की गरिमा को बढ़ाने वाले साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति और देश से माओवाद खत्म होने के बाद आज पूरे देश में भारत का संविधान लागू हो गया है। उन्होंने कहा कि, उत्तराखंड ने संविधान की भावना के अनुरूप, समान नागरिक संहिता लागू कर, पूरे देश को नई राह दिखाई है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का जीवन गरीबों, वंचितों और शोषितों को न्याय पूर्ण व्यवस्था देने के लिए समर्पित रहा है, केंद्र सरकार भी इसी भावना के साथ हर गरीब को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि देश का संतुलित विकास, सबको सुविधा और सबकी समृद्धि ही सामाजिक न्याय का माध्यम बन सकती है। इसलिए बाबा साहेब भी औद्योगिकरण और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भरपूर वकालत करते थे।

प्रधानमंत्री ने देश के विकास में सड़क, रेलवे, रोपवे और वाटरवे की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि कुछ लोग, भविष्य जानने के लिए हाथ की रेखाओं को दिखाने के लिए ज्योतिष शास्त्र की शरण में जाते हैं। आज इसी तरह सड़कें, राष्ट्र की भाग्य रेखाएं बनती जा रही हैं। उन्होनें कहा कि बीते एक दशक से सरकार विकसित भारत के लिए ऐसी ही भाग्यरेखाओं के निर्माण में जुटी हुई है। ये भाग्य रेखाएं, सिर्फ आर्थिकी का आधार नहीं बनेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ी की समृद्धि की गारंटी भी बनेगी और यही मोदी की गारंटी भी है। उन्होंने कहा कि बीते एक दशक में सरकार ने इन विकास रेखाओं के निर्माण में अभूतपूर्व निवेश किया है। वर्ष 2014 तक, पूरे देश के इंफ्रा प्रोजेक्ट पर दो लाख करोड़ भी खर्च नहीं हो पाते थे, जबकि आज यह राशि छह गुना अधिक बढ़कर 12 लाख करोड़ के पार पहुंच चुकी है। इस दौरान अकेले उत्तराखंड में ही, सवा दो लाख करोड़ रुपए के इंफ्रा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी उत्तराखंड के गांवों में सड़कों के इंतजार में पीढ़ियां बूढ़ी हो जाती थी, आज डबल इंजन की सरकार के कारण गांव गांव सड़क पहुंच रही है। इससे वीरान गांव फिर जीवंत हो रहे हैं। चारधाम महामार्ग परियोजना, रेल परियोजना, केदारनाथ, हेमकुंड रोपवे जैसे परियोजनाएं उत्तराखंड की भाग्य रेखाएं बन रही हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत जिस स्पीड और स्केल पर काम कर रहा है, उसकी चर्चा दुनियाभर में हो रही है। उन्होने कहा कि बीते कुछ महीनों के भीतर ही दिल्ली मेट्रो का विस्तार हुआ है, साथ ही मेरठ तक मेट्रो पहुंची है, नोएडा में एयरपोर्ट शुरु हुआ है और अब दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर भी शुरु हो चुका है। इतने छोटे से क्षेत्र में इतना सबकुछ हो रहा है तो आप देशभर की प्रगति का आंकलन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में कई इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम चल रहा है। ये इकोनॉमी कॉरिडार प्रगति के नए द्वार बनने जा रहे हैं जिनसे हमारी उम्मीदों की डोर भी जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली - देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से जहां लोगों का आने जाने में समय बचेगा, वहीं ईंधन की खपत कम होने से किराया और माल भाड़ा भी बचेगा। साथ ही किसानों को अपने उत्पाद, तेजी से बड़ी मंडियों तक पहुंचाने की सुविधा मिलेगी। इस शानदार एक्सप्रेस वे का सर्वाधिक लाभ उत्तराखंड के पर्यटन को मिलेगा ।

प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के लोगों के साथ ही यहां आने वाले पर्यटकों से अपील करते हुए कहा कि वो देवभूमि की धरोहर बहुत पवित्र है, ऐसे स्थानों का साफ सुथरा रखना हम सबका कर्तव्य है। यहां जगह -जगह कूड़ा डालने, प्लास्टिक की बोतलें फेंकने से देवभूमि की पवित्रता को ठेस पहुंचती है। इसलिए देवभूमि के तीर्थ स्थलों को स्वच्छ और सुंदर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले साल हरिद्वार में दिव्य, भव्य और स्वच्छ कुंभ मेले का आयोजन होगा, इसी के साथ उत्तराखंड में जल्द ही नंदा देवी राजजात भी आयोजित होने वाली है। ये यात्रा उत्तराखंड की विशिष्ट सांस्कृतिक चेतना का भी उदाहरण है, जिसमें मां नंदा को बेटी मानकर सम्मान के साथ विदा किया जाता है। उन्होंने कहा कि वो मां नंदा को प्रणाम करते हुए, विकसित भारत के निर्माण में माताओं बहनों की बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की सैन्य परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि देश, 1962 में शहीद हुए बाबा जसवंत सिंह के शौर्य को भुला नहीं सकता। सैनिकों के सम्मान के क्रम में केंद्र सरकार ने वन रैंक, वन पेंशन लागू करते हुए पूर्व सैनिकों के खाते में सवा लाख करोड़ से अधिक की धनराशि जमा की है। जिसका लाभ उत्तराखंड के हजारों परिवारों को भी मिला है। सरकार देशभक्ति, देवभक्ति और प्रगति को जोडते हुए विकसित भारत का संकल्प सच करने का प्रयास कर रही है।

2029 में आधी आबादी को मिलेगा पूरा हक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिलाओं को राजनैतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए, संसद ने चार दशक के बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर दिया है, इससे लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण तय हो गया है। अब इसे लागू करने में देर नहीं होने चाहिए, 2029 के लोकसभा और इससे आगे के विधानसभा चुनावों में इसे लागू किया जाना चाहिए। देश की इसी भावना के अनुरूप 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने सभी दलों से इस संसोधन अधिनियम को समर्थन देने की अपील करते हुए कहा कि, 2029 में देश की पचास प्रतिशत आबादी को उनका हक मिलकर रहेगा।

बारामासी पर्यटन की ओर बढ़ा उत्तराखंड

प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड सरकार द्वारा विंटर टूरिज्म, विंटर स्पोर्ट्स और वेड इन उत्तराखंड जैसे अभियानों को बढ़ावा दिए जाने के लिए जारी प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि, अब उत्तराखंड बारामासी पर्यटन की तरफ बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने 2023 में अपनी आदि कैलाश- ओमपर्वत यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि, पहले यहां साल में कुछ सौ लोग ही आते थे, जबकि 2025 में यह संख्या 40 हजार के पार पहुंच गई है। इसी तरह उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा में आने वाले पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की संख्या भी 80 हजार से बढ़कर डेढ़ लाख पहुंच गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए, प्रगति, प्रकृति और संस्कृति को साथ रखा जाना जरूरी है। इसलिए आज हर निर्माण का इस त्रिवेणी को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें ध्यान देना होगा कि इंसानों के लिए होने वाले विकास कार्यों से वन्य जीवों को कोई कष्ट न हो। इसलिए दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर 12 किमी लंबा एलिवेट रोड बनाया गया है।

महज 10 रुपए के आरोप में रेलवे ने छीनी थी नौकरी

21 साल बाद हाईकोर्ट ने सुनाया ऐसा फैसला कि अधिकारियों की खुल गई पोल

जबलपुर (एजेंसी)। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बेहद भावनात्मक और चौंकाने वाले मामले में अहम फैसला सुनाते हुए रेलवे के एक पूर्व कर्मचारी नारायण नायर की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया है। करीब 21 सालों तक न्याय के लिए भटकने वाले इस कर्मचारी को आखिरकार अदालत से बड़ी राहत मिली है। हैरानी की बात यह है कि इस कर्मचारी को महज 10 रुपये की कथित गड़बड़ी के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया था। हाईकोर्ट के इस फैसले ने सिस्टम की उस संवेदनहीनता को उजागर किया है, जिसमें खुद को निर्दोष साबित करने के लिए एक इंसान को अपनी जिंदगी के दो दशक से ज्यादा का समय खपाना पड़ा।

10 रुपये की कथित गड़बड़ी और बिना सुनवाई छीनी नौकरी

इस अन्याय की कहानी 4 जनवरी 2002 को शुरू हुई थी। उस दिन नारायण नायर श्रीधाम रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। लंबी कतारों और भारी भीड़ के बीच विजिलेंस की एक टीम 'डिकॉय' (फर्जी) यात्री के साथ वहां पहुंची। डिकॉय यात्री ने आरोप लगाया कि नायर को 31 रुपये वापस करने थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 21 रुपये लौटाए और 10 रुपये खुद रख लिए। नायर लगातार कहते रहे कि भारी भीड़ के कारण यह अनजाने में हुई गलती हो सकती है, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। बिना किसी सुनवाई और सफाई का मौका दिए, उनकी सालों की नौकरी सिर्फ 10 रुपये के आरोप में एक झटके में खत्म कर दी गई।

विजिलेंस टीम की ज्यादती यहीं नहीं रुकी। टीम ने दावा किया कि नायर के पास से 450 रुपये अतिरिक्त मिले हैं। नायर ने मिन्नतें कीं कि यह उनकी निजी रकम है जो उन्होंने अपनी बीमार पत्नी की दवा के लिए रखी है, लेकिन अधिकारियों ने इस सफाई को पूरी तरह दरकिनार कर दिया। इसके अलावा, काउंटर के पास जमीन पर पड़े टिकटों के एक बंडल को भी उनके खिलाफ हथियार बना लिया गया, जबकि नायर को उसकी कोई जानकारी ही नहीं थी। जांच के आंकड़ों में भी भारी विसंगतियां थीं। पहले कहा गया कि 778 रुपये ज्यादा मिले हैं, लेकिन बाद की जांच में यह रकम घटकर सिर्फ 7 रुपये रह गई। हालांकि, तब तक नायर अपनी नौकरी और सम्मान दोनों खो चुके थे।

साल 2026 में जब यह मामला आखिरकार हाईकोर्ट पहुंचा, तो अदालत ने पूरे केस की बारीकी से परतें खोलीं। सामने आया कि यह किसी अपराध का नहीं, बल्कि कानूनी प्रक्रिया की घोर विफलता का मामला था। कोर्ट ने हैरान होते हुए पाया कि 10 रुपये के इस कथित आरोप में कोई भी स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था। केवल उस डिकॉय यात्री का बयान था, जो खुद उसी विजिलेंस टीम का हिस्सा था। इसके अलावा किसी भी आम यात्री ने नायर की कभी कोई शिकायत नहीं की थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि मामले का जांच अधिकारी ही अभियोजन पक्ष की भूमिका भी निभा रहा था, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन है।

छोटी चूक के लिए बर्खास्तगी बेहद कठोर और अनुचित सजा

इस पूरे मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि लगाए गए आरोप संभावनाओं के आधार पर भी साबित नहीं होते हैं। अदालत ने ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखते हुए रेलवे की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी की कि अगर मान भी लिया जाए कि कोई छोटी-मोटी चूक हुई थी, तो उसके लिए सीधे नौकरी से बर्खास्त कर देना एक बेहद 'कठोर और असंगत' सजा थी।

1 लाख कमाने वाली पत्नी ने मांगा मेंटिनेंस तो भड़का कोर्ट, कहा- यह तो मांस नोचने जैसा

भोपाल (एजेंसी)। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आर्थिक रूप से सक्षम पत्नी द्वारा मेंटिनेंस (भरण-पोषण) की मांग उचित नहीं ठहराई जा सकती। अदालत ने इस मामले में कड़ी टिप्पणी करते हुए याचिका को खारिज कर दिया और फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।

न्यायमूर्ति Justice Vivek Jain ने सुनवाई के दौरान अंग्रेजी साहित्यकार William Shakespeare के प्रसिद्ध नाटक The Merchant of Venice का उल्लेख करते हुए कहा कि यह मांग वैसी ही प्रतीत होती है, जैसे किसी के शरीर से मांस का टुकड़ा मांगना। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसी मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

अदालत ने पाया कि महिला की मासिक आय 1 लाख से अधिक है, जिससे वह अपना जीवन-यापन आराम से कर सकती है। साथ ही, दंपति का कोई बच्चा भी नहीं है, जिसके पालन-पोषण का अतिरिक्त दायित्व हो।

कोर्ट ने कहा कि मेंटिनेंस का प्रावधान उन परिस्थितियों में लागू होता है, जब पत्नी आर्थिक रूप से निर्भर हो या बच्चों की जिम्मेदारी हो। इस मामले में ऐसा कोई आधार नहीं बनता। इससे पहले 18 फरवरी 2026 को फैमिली कोर्ट ने आदेश दिया था कि तलाक की प्रक्रिया पूरी होने तक महिला को कोई मेंटिनेंस नहीं दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने इस फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। दंपति का विवाह 4 नवंबर 2022 को हुआ था और 2023 से दोनों अलग रह रहे हैं। पति ने तलाक की याचिका दायर की थी, जबकि पत्नी ने अदालत से मेंटिनेंस की मांग की थी। अदालत ने अपने फैसले में दोहराया कि मेंटिनेंस का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर या आश्रित जीवनसाथी की सहायता करना है, न कि पहले से सक्षम व्यक्ति को अतिरिक्त लाभ देना।

आय को लेकर दोनों पक्षों के तर्क

याचिका में महिला ने स्वीकार किया था कि वह नौकरी करती हैं और पहले उनकी वार्षिक आय करीब 20 लाख थी, जबकि उनके पति की आय 30 लाख से अधिक बताई गई। बाद में महिला ने अदालत में कहा कि उनकी आय घटकर लगभग 14 लाख सालाना रह गई है। हालांकि, हाई कोर्ट ने कहा कि यदि इस आंकड़े को भी स्वीकार किया जाए, तब भी महिला की मासिक आय लगभग 1.25 लाख बनती है, जो उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाती है।

महिलाओं को हर महीने 2000 रू., 3 फ्री एलपीजी सिलेंडर और फास्ट ट्रैक कोर्ट

तमिलनाडु में बीजेपी का मेनिफेस्टो जारी

चेन्नई (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कई कल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक सुधारों का वादा किया गया है। उन्होंने सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) सरकार पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप भी लगाए। उन्होंने डीएमके पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कई नेताओं को घोटालों से जोड़कर भ्रष्टाचार का संरक्षक बताया।

घोषणा पत्र में महिलाओं के मुखिया वाले परिवारों को हर महीने 2,000 रुपये देने का वादा किया गया है। इसके अलावा हर साल 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर और प्रत्येक परिवार को एकमुश्त 10,000 रुपये देने की बात कही गई है। योग्य महिलाओं को ई-स्कूटर खरीदने के लिए 25,000 रुपये की सब्सिडी और जल्लीकट्टू बैलों की देखभाल करने वालों को 2,000 रुपये मासिक सहायता देने का भी प्रस्ताव किया गया है। बता दें, राज्य में 23 अप्रैल को चुनाव होने हैं।

घोषणापत्र में पहली बार घर खरीदने वाली महिलाओं को स्टांप ड्यूटी में 3 प्रतिशत की छूट देने का वादा किया गया है। साथ ही, 10,000 रुपये की एकमुश्त सहायता और घरेलू सामान के लिए 8,000 रुपये के कूपन देने की भी योजना है। प्रमुख मंदिरों में स्थानीय निवासियों के लिए रोजाना दो घंटे का दर्शन स्लॉट और कार्तिगई दीपम परंपरा को जारी रखने का भी प्रस्ताव रखा गया है।

घोषणापत्र में बसों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना भी शामिल है, जिससे सुरक्षा और निगरानी को मजबूत किया जा सके।

बाबा साहेब के विचारों पर बना है देश, रक्षा के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे : राहुल गांधी

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि यह देश बाबासाहेब के विचारों पर बना है। वे पूरी शक्ति के साथ आखिरी दम तक इनकी रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर ने हमें सिर्फ संविधान नहीं, न्याय, समानता और सम्मान पर आधारित एक सशक्त भारत का सपना दिया। लेकिन आज कुछ ताकतें सुनियोजित तरीके से बाबासाहेब की इस विरासत और हमारे संविधान को कमजोर करने में लगी हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं को खोखला किया जा रहा है, अधिकारों को कुचला जा रहा है और समता की सोच पर हमला हो रहा है।

उन्होंने आगे लिखा, यह देश बाबासाहेब के विचारों पर बना है। मैं पूरी शक्ति के साथ आखिरी दम तक इनकी रक्षा के लिए लड़ता रहूंगा। हम सब मिल कर बाबा साहेब के सपनों के भारत को फिर से साकार करेंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने सभी को अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं दी।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बाबासाहेब अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, बाबासाहेब अंबेडकर की जयंती पर हम उस दूरदर्शी महापुरुष को नमन करते हैं, जिन्होंने भारत को उसकी नैतिक और संवैधानिक आत्मा प्रदान की। बाबासाहेब न सिर्फ भारत के संविधान के निर्माता थे, बल्कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय के लिए एक अथक योद्धा भी थे। ये वे मूल्य हैं जो भारत के मूल विचार को परिभाषित करते हैं।

उन्होंने आगे लिखा, आज, जब संविधान एक षड्यंत्रकारी हमले का सामना कर रहा है, तब उनके शब्द और उनकी चेतावनियां एक नई और गहन प्रासंगिकता के साथ गूंज रही हैं। यह एक ऐसा क्षण है जो साहस और दृढ़ विश्वास की मांग करता है। हमें केवल उन्हें याद ही नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उठ खड़े होकर उनके की ओर से स्थापित हर सिद्धांत की रक्षा करनी चाहिए। उनकी ओर से सुनिश्चित किए गए हर अधिकार को सुरक्षित रखना चाहिए। इसके साथ ही, उन सभी मूल्यों को अक्षुण्ण रखना चाहिए जिनके लिए वे जिए और जिनके लिए उन्होंने संघर्ष किया

वहीं, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि संविधान निर्माता बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर ने हर एक भारतीय को संविधान के रूप में एक सुरक्षाकवच दिया, जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व की गारंटी है। उन्होंने पोस्ट में लिखा, बाबासाहेब के अथक प्रयासों से वंचित वर्गों के सवाल हमारे स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान का अभिन्न हिस्सा बने।

नोएडा में हिंसा के बाद एक्शन, 300 गिरफ्तारियां

नोएडा (एजेंसी)। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर नोएडा में श्रमिकों का प्रदर्शन हिंसक हो गया। जगह-जगह उपद्रव और आगजनी की घटनाओं के बाद पुलिस ने 300 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है और सात एफआईआर दर्ज की गई हैं। साथ ही, व्हाट्सएप ग्रुप्स की भी जांच की जा रही है।

इकोटेक-3 थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन के दौरान गोली लगने से एक महिला श्रमिक के घायल होने के बाद से ही माहौल तनावपूर्ण था। सुबह श्रमिक डंडे और पत्थर लेकर सड़कों पर उतर आए और जिले के तीन औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापक हिंसा फैल गई। प्रदर्शनकारियों ने 500 से अधिक औद्योगिक इकाइयों में तोड़फोड़ की और पुलिस वाहनों समेत 20 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। एनएच-9 और नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे सहित कई प्रमुख मार्गों पर यातायात बाधित रहा।

अखिलेश ने सीएम योगी पर साधा निशाना

नोएडा में हुए बवाल पर बोले यह सरकार की नाकामी

लखनऊ (एजेंसी)। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाए कि नोएडा की घटना को लेकर मुख्यमंत्री (योगी आदित्यनाथ) और भाजपा सरकार जिम्मेदार है। अखिलेश यादव ने भीमराव अंबेडकर की जयंती पर लखनऊ में हजरतगंज चौराहा पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।

इसी दौरान नोएडा में हुए हिंसक प्रदर्शन पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, जो नोएडा में हुआ है, यह सरकार की नाकामी के कारण हुआ है। सरकार को मामले की जानकारी थी, फिर भी ऐसी घटना होने दी। अगर अधिकारी कह रहे कि साजिश हुई है तो इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। सपा प्रमुख ने आगे कहा, मुख्यमंत्री से ज्यादा झूठ बोलने वाला कोई संत अभी तक नहीं हुआ है। हम नहीं कहते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वे नकली संत हैं। इन्हें संविधान से कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि संविधान से चलने वाले कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं।

उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा की 10 साल की सरकार में बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर की बड़ी संख्या में प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाया गया है। आज वही लोग जो ऐसे कृत्यों में शामिल थे, चुनावों से पहले एक गुमराह करने वाला संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा की साजिश और षड्यंत्रों से सावधान है और वह समझदार भी है। अखिलेश यादव ने कहा, हम सामाजिक न्याय के लिए और सामाजिक न्याय की व्यवस्था स्थापित करने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। यह संघर्ष वर्षों तक, और अगर जरूरत पड़ी तो सदियों तक जारी रहेगा।

सोने-चांदी की कीमतों में अचानक आई भारी गिरावट, औंधे मुंह गिरे भाव

नई दिल्ली (एजेंसी)। हफ्ते के पहले ही दिन सर्राफा बाजार से ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। शुरुआती रुझानों में सोने और चांदी दोनों ही बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। अगर आप भी शादी-ब्याह या किसी अन्य मौके के लिए गहने खरीदने का मन बना रहे हैं, तो यह आपके लिए एक अच्छा अवसर साबित हो सकता है।

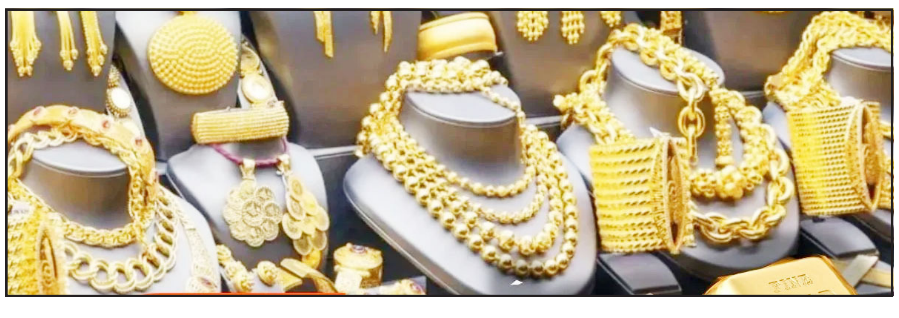

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सुबह दोनों धातुओं के भाव लाल निशान पर कारोबार करते दिखे। सुबह 10:15 बजे के आंकड़ों के अनुसार, 5 जून 2026 की डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध में बीते सत्र के मुकाबले 0.63 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद इसका भाव 1,51,686 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं, चांदी की कीमतों में सोने से भी ज्यादा गिरावट देखी गई। 5 मई 2026 की डिलीवरी वाले चांदी के अनुबंध की कीमत 2.10 प्रतिशत टूटकर 2,38,163 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई।

हाजिर बाजार में भी देश के प्रमुख शहरों में सोने के दामों में बदलाव देखने को मिला है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां 24 कैरेट सोने का भाव 15,261 रुपये प्रति ग्राम है, जबकि 22 कैरेट 13,990 रुपये और 18 कैरेट 11,449 रुपये प्रति ग्राम बिक रहा है। आर्थिक राजधानी मुंबई के साथ-साथ कोलकाता और बेंगलुरु में सोने के दाम एक समान रहे। इन तीनों शहरों में 24 कैरेट सोना 15,246 रुपये, 22 कैरेट 13,975 रुपये और 18 कैरेट 11,434 रुपये प्रति ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वहीं, चेन्नई में सोना अन्य शहरों के मुकाबले थोड़ा महंगा बिक रहा है। यहां 24 कैरेट सोने का भाव 15,338 रुपये, 22 कैरेट 14,060 रुपये और 18 कैरेट 11,730 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया है। वैश्विक बाजार की बात करें तो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के आंकड़ों के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोमवार को सोने की कीमतों में करीब 2 फीसदी की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट के बाद सोना 4,700 डॉलर प्रति औंस के अहम स्तर से नीचे खिसक गया है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले सप्ताह की भारी तेजी के बाद यह गिरावट मुख्य रूप से वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव के कारण आई है।

अमेरिका द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य पर प्रतिबंध लगाने की योजना और ईरान के साथ वार्ता विफल होने के कारण वैश्विक ऊर्जा संकट को लेकर चिंताएं काफी बढ़ गई हैं, जिसका सीधा असर अब सर्राफा बाजार की चाल पर देखने को मिल रहा है।

रेलवे नौकरी अलर्ट

केआरसीएल में 2 पदों पर भर्ती जारी, 63 साल तक के उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन

अमरावती (एजेंसी)। भारतीय रेलवे में नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड (केआरसीएल) ने वर्क मैनेजर और असिस्टेंट वर्क मैनेजर के कुल दो पदों पर भर्ती के लिए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर वैकेंसी निकाली है।

केआरसीएल की ओर से जारी पदों के लिए ऑनलाइन (ईमेल) के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू हो गई है और आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की गई है। ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, उन्हें तय समय सीमा के भीतर अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की सलाह दी जाती है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त (एआईसीटीई) विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/मैकेनिकल/प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमा होना चाहिए। इसी के साथ कैंडिडेट्स भारतीय रेलवे/भारतीय रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सेवानिवृत्त यांत्रिक विभाग के अधिकारी होने चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट्स के पास तय सालों का अनुभव होना भी अनिवार्य है।

उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 63 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसकी गणना 10 अप्रैल के आधार पर की जाएगी। वहीं, चयनित अभ्यर्थियों की सैलरी 39,100 से 15,600 रुपए के बीच प्रति माह होगी। इसी के साथ कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे। वहीं, उम्मीदवारों की पोस्टिंग वडालापुडी कार्यशाला, विशाखापत्तनम में होगी।

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले केआरसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर जाने के बाद संबंधित पद के लिए जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करें।

ईरान युद्ध से वैश्विक अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका, आईएमएफ प्रमुख की चेतावनी

वाशिंगटन (एजेंसी)। आईएमएफ (अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष) की प्रमुख ने कहा कि ईरान युद्ध ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका दिया है। इसकी वजह से ऊर्जा की सप्लाई बाधित हो गई है और पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इसका असर आने वाले साल तक महसूस होता रहेगा। आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने सीबीएस न्यूज के एक इंटरव्यू में कहा कि इस रुकावट का पैमाना और अवधि ही इसके दीर्घकालिक परिणामों को निर्धारित करेगी। उन्होंने आगाह किया कि इसके प्रभाव पहले से ही व्यापक हैं।

उन्होंने कहा, मैं आपको यह बता सकती हूं कि यह झटका बहुत बड़ा है। दुनिया का लगभग 13 प्रतिशत तेल और 20 प्रतिशत गैस, जो सामान्य रूप से सप्लाई होती, वह अब पिछले पांच हफ्तों से अटकी हुई है, जिससे सप्लाई की गंभीर स्थिति समझ आती है। उन्होंने कहा कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, लेकिन हर देश पर अलग तरह से। हर कोई ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। हर कोई बढ़ती कीमतों का असर महसूस कर रहा है और यह अलग-अलग देशों पर अलग तरीके से असर डालता है। ऊर्जा पर निर्भर देश और संघर्ष के पास वाले इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जबकि कम आय वाले देशों पर इसका दबाव और भी ज्यादा है क्योंकि उनके पास संसाधन सीमित हैं।

जॉर्जीवा ने बताया कि इसका असर अब कई क्षेत्रों में दिखने लगा है जैसे ईंधन की कमी, खाद की सप्लाई में दिक्कत, ट्रांसपोर्ट और विदेश से आने वाले पैसों पर भी। उन्होंने कहा कि लोग परेशान हैं, और कई जगहों पर सामान की भारी कमी हो रही है। जरूरी चीजें ही उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने यह भी बताया कि एशिया के कई हिस्सों में ऊर्जा की राशनिंग और सप्लाई की कमी से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। साथ ही चेतावनी दी कि खाद की कीमतें बढ़ने से दुनिया भर में खाने-पीने की चीजें भी महंगी हो सकती हैं।

आईएमएफ प्रमुख ने यह भी कहा कि भले ही संघर्ष रुक जाए, फिर भी इसका असर तुरंत खत्म नहीं होगा। यह असर पहले ही सिस्टम में बैठ चुका है। देरी से हुई सप्लाई और बुनियादी ढांचे को नुकसान लंबे समय तक असर डालता रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ जरूरी ऊर्जा उत्पादन सुविधाओं को पूरी तरह ठीक होने में तीन से पांच साल तक लग सकते हैं। उन्होंने अमेरिका के बारे में बात करते हुए कहा कि वहां असर बाकी दुनिया के मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन बढ़ती कीमतें महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिशों को मुश्किल बना सकती हैं। उन्होंने कहा कि आईएमएफ को उम्मीद थी कि 2026 में वैश्विक विकास बेहतर होगा, लेकिन अब इस युद्ध की वजह से यह अनुमान कम हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि संघर्ष कितने समय तक चलता है और उत्पादन कितनी जल्दी ठीक होता है।

जंग की आहट से शेयर बाजार में भूचाल

मुंबई (एजेंसी)। अमेरिका-ईरान में युद्ध थमता नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान में शांति वार्ता फेल होने के बाद अचानक कच्चे तेल की कीमतों में आए जोरदार उछाल ने एक बार फिर से शेयर बाजारों का मूड खराब कर दिया है। भारतीय शेयर बाजार में बीते सप्ताह की तेजी पर ब्रेक लग गया है और ओपनिंग के साथ ही ये क्रैश हो गया।

बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स खुलते ही 1600 अंकों से ज्यादा का गोता लगा गया, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स 490 अंक के आसपास फिसल गया। इस बीच IndiGo, Bajaj Finance, Asian Paints से लेकर HDFC Bank तक के शेयर धराशायी नजर आए।

शेयर मार्केट में कारोबार की शुरुआत होने के साथ ही बीएसई का सेंसेक्स अपने पिछले बंद 77,550 की तुलना में तेज गिरावट के साथ 75,937 के लेवल पर ओपन हुआ और महज कुछ सेकंड में ये गिरते हुए 75,868 पर आ गया। इस बीच एनएसई का निफ्टी-50 भी भरभराकर टूटा और अपने पिछले बंद 24,050 की तुलना में 23,589 पर खुला।

सीजफायर टूटा तो दुनिया पर आएगा बड़ा संकट! वर्ल्ड बैंक के चीफ की चेतावनी, हालात होंगे बेकाबू

नई दिल्ली (एजेंसी)। ईरान से जुड़े भू-राजनीतिक तनाव के आर्थिक प्रभाव अब धीरे-धीरे वैश्विक स्तर पर दिखने लगे हैं। इस बीच विश्व बैंक के अध्यक्ष Ajay Banga ने दुनिया को आगाह किया है कि मौजूदा सीजफायर अगर टूटता है, तो इसके नतीजे बेहद गंभीर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि भले ही युद्ध फिलहाल थम जाए, लेकिन इसका असर लंबे समय तक वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बना रहेगा।

अजय बंगा के मुताबिक, यदि सीजफायर कायम रहता है तो भी वैश्विक आर्थिक विकास दर में 0.3 प्रतिशत से 0.4 प्रतिशत तक गिरावट संभव है। वहीं, अगर हालात बिगड़ते हैं और संघर्ष दोबारा तेज होता है, तो यह गिरावट 1 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। इसका सीधा असर व्यापार, ऊर्जा बाजार और वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर पड़ेगा। इस संकट का असर महंगाई पर भी साफ दिख सकता है। अनुमान के मुताबिक, सीजफायर जारी रहने की स्थिति में महंगाई 0.2 प्रतिशत से 0.3 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। लेकिन अगर संघर्ष लंबा खिंचता है, तो यह बढ़कर 0.9 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। खासकर विकासशील देशों के लिए यह स्थिति अधिक चुनौतीपूर्ण होगी, जहां महंगाई दर 6.7 प्रतिशत तक जा सकती है।

ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भर देशों के लिए यह संकट और गंभीर हो सकता है। विश्व बैंक पहले ही ऐसे देशों के साथ संवाद कर रहा है, जो ऊर्जा आयात पर अधिक निर्भर हैं। छोटे द्वीपीय देशों के लिए स्थिति और कठिन हो सकती है, जिसके मद्देनजर इमरजेंसी फंडिंग की तैयारी की जा रही है। अजय बंगा ने सरकारों को चेताया कि वे अल्पकालिक राहत देने वाली लेकिन दीर्घकाल में अस्थिर ऊर्जा सब्सिडी से बचें। उन्होंने जोर देकर कहा कि देशों को अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लानी चाहिए, ताकि भविष्य में आर्थिक अस्थिरता से बचा जा सके। बंगा ने नाइजीरिया का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां 20 अरब डॉलर की रिफाइनरी परियोजना ने देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया है। इससे न केवल आत्मनिर्भरता बढ़ी है, बल्कि पड़ोसी देशों को ईंधन निर्यात करने की क्षमता भी विकसित हुई है।

उन्होंने कहा कि परमाणु, पवन, सौर और जलविद्युत जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर निवेश बढ़ाना समय की जरूरत है, वरना दुनिया फिर पारंपरिक ईंधन पर निर्भर होकर आर्थिक और पर्यावरणीय जोखिम बढ़ा सकती है।

खुदरा मुद्रास्फीति मार्च में मामूली बढ़कर 3.4 प्रतिशत पर

नई दिल्ली (एजेंसी)।

सरकार ने खुदरा मुद्रास्फीति का आंकड़ा जारी किया. जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में खुदरा मुद्रास्फीति मार्च में सालाना आधार पर 3.40 प्रतिशत तक पहुंच गई, जो फरवरी में 3.21 प्रतिशत थी.

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा, 2024 को आधार वर्ष मानते हुए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मार्च 2026 से मार्च 2025 तक की सालाना मुद्रास्फीति दर 3.40 प्रतिशत (अस्थायी) है. आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण मुद्रास्फीति 3.63 प्रतिशत रही, जबकि शहरी मुद्रास्फीति 3.11 प्रतिशत पर बनी रही. खाद्य मुद्रास्फीति 3.87 फीसदी अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) द्वारा मापी गई खाद्य मुद्रास्फीति मार्च 2026 में वार्षिक आधार पर 3.87 प्रतिशत रही. ग्रामीण क्षेत्रों में यह 3.96 प्रतिशत थी, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 3.71 प्रतिशत थी.

प्रमुख सब्जियों की कीमतों में भारी गिरावट - कुछ आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई. प्याज की कीमतों में 27 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई, जबकि आलू की कीमतों में लगभग 19 प्रतिशत की कमी देखी गई. लहसुन, अरहर (तुअर) और चने जैसी दालों की कीमतों में भी गिरावट आई, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली.

खाद्य पदार्थों में, टमाटर और फूलगोभी की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, हालांकि यह फरवरी के स्तर से कम थी.कुछ वस्तुओं की कीमतों में भारी उछाल आया. चांदी के आभूषणों की मुद्रास्फीति लगभग 148 प्रतिशत पर बनी रही, जबकि सोने और हीरे के आभूषणों की कीमतों में लगभग 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई.आवास मुद्रास्फीति कम बनी हुई है.मार्च 2026 के लिए आवास मुद्रास्फीति का अस्थायी अनुमान 2.11 प्रतिशत लगाया गया है. इस श्रेणी में, ग्रामीण आवास मुद्रास्फीति 2.54 प्रतिशत पर अधिक थी, जबकि शहरी आवास मुद्रास्फीति 1.95 प्रतिशत रही.

कच्चे तेल की कीमत में आया उछाल

मुंबई (एजेंसी)। कच्चे तेल की कीमत में 10 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली है, जिससे दाम फिर से 100 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गया है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल की वजह ईरान से वार्ता विफल होने के बाद अमेरिका का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक करना है। सुबह 10:45 पर ब्रेंट क्रूड का दाम 7.41 प्रतिशत या 7.05 डॉलर बढ़कर 102.2 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई क्रूड का दाम 8.54 प्रतिशत या 8.25 डॉलर बढ़कर 104.8 डॉलर प्रति बैरल हो गई है।

घरेलू स्तर पर भी कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर क्रूड ऑल फ्यूचर्स (20 अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट) 7.61 प्रतिशत या 697 रुपए बढ़कर 9,850 रुपए पर था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान जलमार्ग को खुला रखने में विफल रहा है और चेतावनी दी कि अमेरिका स्ट्रेट में प्रवेश करने या बाहर निकलने की कोशिश करने वाले सभी जहाजों को रोकेगा। उन्होंने समुद्री सुरक्षा और वैश्विक तेल आपूर्ति में संभावित व्यवधान को लेकर चिंता व्यक्त की। अमेरिका और ईरान ने 8 अप्रैल को दो सप्ताह के युद्धविराम पर सहमति जताई थी, जिसका उद्देश्य तनाव कम करना और एक महत्वपूर्ण वैश्विक तेल पारगमन मार्ग, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलना सुनिश्चित करना था।

धोनी को देखने के लिए करना होगा इंतजार, मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलने की संभावना

नई दिल्ली (एजेंसी)।

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को खेलते देखने का इंतजार एक हफ्ते और बढ़ गया है। वह मुंबई इंडियंस के खिलाफ वानखेड़े में 23 अप्रैल को खेलते दिख सकते हैं। 44 साल के धोनी सीजन से पहले कैंप में पिंडली में खिंचाव से जूझ रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के सूत्रों के अनुसार वह पूरी तरह से फिट होने के करीब हैं। चेन्नई सुपर किंग्स का अगला मैच सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हैदराबाद में है, लेकिन इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि धोनी टीम के साथ यात्रा करेंगे या नहीं।

आईपीएल 2026 की अंक तालिका में चेन्नई सुपर किंग्स 8वें नंबर पर है। वह पांच में से दो मैच जीती है। ऋतुराज गायकवाड़ की अगुआई वाली टीम लगातार तीन मैच हारी। इसके बाद उसने दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स को पिछले दो मैचों में हराया। चेन्नई सुपर किंग्स के घरेलू मैचों के दौरान भी धोनी होटल में ही रहते हैं। हालांकि, वह अभ्यास सत्र में दिखे हैं। थ्रोडाउन लेते हुए उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई है।

चेन्नई सुपर किंग्स का पिछले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स से मुकाबला हुआ था। इस मैच से पहले अभ्यास सत्र में बल्लेबाजी कोच माइकल हसी की देखरेख में बल्लेबाजी की थी, लेकिन उन्होंने प्रमुख गेंदबाजों का सामना नहीं किया। उन्होंने चाइनामैन स्पिनर नूर अहमद के साथ समय बिताया। सीएसके के गेंदबाजी कोच श्रीधरन श्रीराम ने कहा, 'एमएस (धोनी) ने एक अभ्यास सत्र में उनसे लंबी बातचीत की और उनकी लेग ब्रेक को ठीक कराया। मेरे हिसाब से यह उनके लिए बहुत मददगार रहा और नतीजे भी दिखे।'

प्लेइंग 11 में कैसे फिट होंगे धोनी

थ्रोडाउन लेते वक्त धोनी बगैर किसी दिक्कत के शॉट लगाते दिखे। दो मैच जीतने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स को धोनी को प्लेइंग 11 में फिट करने के लिए रास्ते तलाशने होंगे। चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी में गहराई नहीं है। गेंदबाज नंबर 8 पर खेल रहे हैं। धोनी को प्लेइंग 11 में सरफराज खान की जगह मौका मिल सकता है। सरफराज ने अच्छी बल्लेबाजी की है, लेकिन वह कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ तेजी से बल्लेबाजी करने में संघर्ष करते दिखे। उन्होंने 18 गेंद पर 23 रन बनाए। धोनी को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खिलाने का भी विकल्प है।

मुंबई इंडियंस को झटका, पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच से बाहर हो सकते हैं रोहित शर्मा

नई दिल्ली (एजेंसी)। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच से पहले मुंबई इंडियंस को झटका लगा है। रोहित शर्मा पिछले मैच से लगभग बाहर हो गए हैं। फिलहाल वह टीम के मेडिकल स्टाफ की निगरानी में हैं। पिछले रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ बड़े स्कोर वाले मैच के दौरान मुंबई इंडियंस की पारी के छठे ओवर में रोहित को पैर की मांसपेशियों में परेशानी महसूस हुई थी। इसके बाद वह मैदान से बाहर चले गए थे।

रोहित शर्मा रिटायर्ड हर्ट होकर बाहर गए तब वह 13 गेंद पर 19 रन बनाकर खेल रहे थे। इसके बाद मुंबई इंडियंस यह मैच 18 रन से हार गई जो मौजूदा सत्र में टीम की लगातार तीसरी हार थी। मुंबई इंडियंस के ट्रेनिंग सत्र के दौरान बुधवार (15 अप्रैल) को टीम के एक अधिकारी ने रोहित को लेकर कहा, 'मेडिकल टीम और कोचिंग स्टाफ उनकी जांच कर रहे हैं और हमें जल्द ही पता चल जाएगा।'

इस बीच इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स जल्द ही मुंबई इंडियंस से जुड़ने वाले हैं। वह मौजूदा सत्र में अब तक टीम के चारों मैच से बाहर रहे हैं और गुरुवार (16 अप्रैल) को भी नहीं खेल पाएंगे। जैक्स और न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर (अब तक दो मैच खेले हैं) ने भारत में टीम से जुड़ने से पहले कुछ और समय मांगा था।

मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2026 की शुरुआत जीत के थी। उसने पहला मैच जीतकर 13 साल का सूखा खत्म किया, लेकिन इसके बाद वह लगातार तीन मैच हारी। वह अंक तालिका में 9वें नंबर पर है। मुंबई इंडियंस के लिए गुरुवार (16 अप्रैल) को पंजाब किंग्स के खिलाफ जीतना जरूरी है। ऐसा न होने पर प्लेऑफ में पहुंचने की संभावनाओं को चोट पहुंचेगी। महेंद्र सिंह धोनी मैच फिट होने के करीब हैं। 44 साल के चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान पिंडली की चोट से जूझ रहे हैं। वह नेट्स में बगैर दिक्कत के शॉट लगाते दिखे।

मुनाफ पटेल ने लगाए एनसीए में ठीक से काम न होने का आरोप

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की देखभाल की जिम्मेदारी बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट एकेडमी (अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) पर होती है। सीओई खिलाड़ियों के शरीर और फिटनेस का ध्यान रखता है, चोटिल होने पर वह वही रिहैब करते हैं। भारत के पूर्व क्रिकेटर मुनाफ पटेल ने एनसीए के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि फिजियो और ट्रेनर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। मुनाफ ने कहा कि एनसीए को 100 प्रतिशत बदलना होगा। वह आज भी उसी ढर्रे पर चल रहा जिस पर वह 2000 में शुरू होने पर चल रहा था, जबकि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की ऐसी व्यवस्था दर्जनों बार बदलाव से गुजरी है।

संपादकीय

आत्म-निरीक्षण का विषय

विदेश मंत्री एस. जयशंकर के लिए यह आत्म-निरीक्षण का विषय होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय मसलों में आज भारत की कोई भूमिका क्यों नहीं बची है? फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्यों अलग-थलग नजर आया?

जब ये साफ हो गया कि प्रधानमंत्री भाग नहीं लेंगे, तो ईरान युद्ध पर बुलाई गई सर्वदलीय महज रस्म-अदायगी भर रह गई। ऐसी बैठकों की तभी अहमियत होती है, जब उनका मकसद उत्पन्न परिस्थिति पर पूरी पारदर्शिता बरतते हुए सभी पक्षों के बीच आम-सहमति बनाना होता है। ऐसा तभी हो सकता है, जब देश के शीर्ष नेता बैठक में उपस्थित रहें। और सिर्फ तभी किसी संकट काल में पूरा देश एक स्वर में बोल सकता है। बहरहाल, नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में ऐसी राष्ट्रीय एकजुटता दुर्लभ होती चली गई है। नतीजतन, सर्वदलीय बैठकें सियासी नैरेटिव को प्रचारित करने का एक और मौका बन जाती हैं।

यही हाल पश्चिम एशिया में युद्ध पर बुलाई गई बैठक का हुआ। विपक्ष ने उसे अपने इस कथानक को बल देने का अवसर बनाया कि मोदी सरकार की कूटनीतिक विफलताओं ने भारतीय आवाम को गहरी मुसीबत में डाल दिया है, जबकि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में भारत अप्रासंगिक होता जा रहा है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान के मध्यस्थ बन कर उभरने की चर्चा हुई। तो उस पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने हैरतअंगेज टिप्पणी की।

उन्होने कहा कि भारत पाकिस्तान की तरह दलाली नहीं कर सकता! अमेरिका ने पाकिस्तान को क्यों मध्यस्थ बनाया और ये भूमिका स्वीकार कर पाकिस्तान ने क्या जोखिम मोल लिए हैं, ये दीगर सवाल हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता को दलाली बताना अपनी विदेश नीति की घोर विफलता से पैदा हुए असंतोष का ही इज़हार समझा जाएगा। वरना, कोरिया युद्ध, कॉन्गो युद्ध, श्रीलंका के गृह युद्ध आदि में मध्यस्थता का भारत के बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है। यहां तक कि यूक्रेन युद्ध में प्रधानमंत्री मोदी ने संवाद और कूटनीतिक समाधान के संदेश दोनों पक्षों को दिए। अतः जयशंकर के लिए यह आत्म-निरीक्षण का विषय होना चाहिए कि आज अंतरराष्ट्रीय मसलों में भारत की कोई भूमिका क्यों नहीं है? बात यहीं तक नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह अलग-थलग नजर आया, वह हालिया तजुर्बा है। इन सवालों पर गौर करने के बजाय दलाल ना होने का झूठा फ़ख्र किसी काम का नहीं है। उससे भारतीय जनमत के सिर्फ एक हिस्से को ही बहलाया जा सकता है।

परिसीमन मुद्दे पर उत्तर बनाम दक्षिण का नैरेटिव खड़ा कर रहे नेताओं से कुछ सवाल

केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच परिसीमन को लेकर छिड़ा विवाद अब राजनीतिक टकराव के नए चरण में पहुंच चुका है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा राज्य भर में काला झंडा प्रदर्शन की घोषणा ने इस मुद्दे को और अधिक तीखा बना दिया है। यह विवाद उत्तर और दक्षिण के बीच राजनीतिक शक्ति संतुलन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कई सवाल खड़े करता है।

देखा जाये तो परिसीमन का अर्थ है जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों का पुनर्निर्धारण और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्गठन। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार यह प्रक्रिया प्रत्येक जनगणना के बाद होनी चाहिए। वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटें 1971 की जनगणना पर आधारित हैं, क्योंकि लंबे समय से परिसीमन पर रोक लगी हुई थी ताकि जनसंख्या नियंत्रण में सफल राज्यों को नुकसान नहीं हो। अब केंद्र सरकार इस रोक को हटाकर 2011 की जनगणना के आधार पर नई व्यवस्था लागू करना चाहती है और सीटों की संख्या को बढ़ाकर लगभग 850 तक करने का प्रस्ताव है।

केंद्र का तर्क है कि देश की जनसंख्या संरचना में भारी बदलाव आया है और प्रतिनिधित्व को वास्तविक स्थिति के अनुरूप बनाया जाना आवश्यक है। साथ ही महिला आरक्षण को लागू करने के लिए भी यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन दक्षिण के कई नेता इस प्रस्ताव को संदेह की नजर से देख रहे हैं।

एमके स्टालिन ने इसे दक्षिणी राज्यों के खिलाफ पक्षपात बताया है। उनका कहना है कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता पाई, उन्हें इस प्रक्रिया के जरिए दंडित किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि केंद्र सरकार ने उनकी चिंताओं को नजरअंदाज किया तो उसे भारी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने इस मुद्दे को केवल तमिलनाडु का नहीं बल्कि संघीय ढांचे की रक्षा का सवाल बताया है।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी इस प्रस्ताव पर गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक शक्ति को कमजोर कर सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि एक संतुलित मॉडल अपनाया जाए जिसमें जनसंख्या के साथ-साथ आर्थिक योगदान को भी ध्यान में रखा जाए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी चेतावनी दी है कि यह प्रक्रिया कुछ बड़े राज्यों के पक्ष में शक्ति का केंद्रीकरण कर सकती है और संघीय संतुलन को बिगाड़ सकती है।

देखा जाये तो यहां तक तो बहस एक लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा लगती है, लेकिन जिस तरह से इसे उत्तर बनाम दक्षिण की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, वह चिंताजनक है। भारत एक संघीय गणराज्य है जहां सभी राज्यों की समान भागीदारी और राष्ट्रीय एकता सर्वोपरि है। ऐसे में क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काना और राजनीतिक लाभ के लिए विभाजन की रेखाएं खींचना एक गलत मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम का बयान भी कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने दावा किया कि परिसीमन से दक्षिणी राज्यों की आवाज दब जाएगी और संसद सत्र को चुनाव के समय बुलाना एक सुनियोजित साजिश है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि परिसीमन एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसे समय समय पर लागू किया जाना आवश्यक है। इसे साजिश या राजनीतिक चाल बताना क्या देश की संस्थाओं पर अनावश्यक संदेह पैदा नहीं करता? चिदंबरम जैसे वरिष्ठ नेता, जो देश के गृह मंत्री रह चुके हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वह तथ्यों और संतुलित दृष्टिकोण के साथ अपनी बात रखें। यदि तमिलनाडु की सीटें बढ़कर 39 से 58 तक पहुंच सकती हैं, जैसा उन्होंने स्वयं कहा, तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि राज्य की आवाज पूरी तरह दब जाएगी? यह तर्क स्वयं में विरोधाभासी प्रतीत होता है।

दरअसल, इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का मूल सिद्धांत नहीं है? यदि किसी क्षेत्र की जनसंख्या अधिक है, तो उसका प्रतिनिधित्व भी अधिक होना स्वाभाविक है। साथ ही यह भी सही है कि विकास और जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए इस मुद्दे पर संतुलित और व्यावहारिक समाधान की आवश्यकता है, न कि राजनीतिक ध्रुवीकरण की। दक्षिणी राज्यों के नेताओं को चाहिए कि वह इस विषय पर संवाद और सहमति की दिशा में आगे बढ़ें, न कि विरोध और टकराव की राजनीति को बढ़ावा दें। केंद्र सरकार को भी सभी राज्यों की चिंताओं को गंभीरता से सुनते हुए ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जो न्यायसंगत और सर्वमान्य हो ।राजनीति

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने घोषणा की है कि INDIA ब्लॉक के तहत एकजुट विपक्षी दल संसद में प्रस्तावित परिसीमन विधेयक का कड़ा विरोध करेंगे। नई दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में विपक्षी नेताओं की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में खरगे ने कहा कि यह विधेयक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को कमजोर कर सकता है और सरकार ने इसे बिना जनगणना पूरी किए पेश किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यपालिका संवैधानिक संस्थाओं की शक्तियों को अपने हाथ में ले रही है और परिसीमन के जरिए कभी भी सीमाओं में बदलाव कर सकती है। देखा जाये तो तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और आम आदमी पार्टी सहित कई दलों की मौजूदगी में हुई इस बैठक को 16 अप्रैल से शुरू हो रहे संसद सत्र से पहले विपक्षी एकजुटता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। विपक्ष का मानना है कि यह विधेयक हिंदी भाषी राज्यों को लाभ पहुंचाकर दक्षिण और पूर्वी राज्यों के प्रभाव को कम कर सकता है। बहरहाल, इसमें कोई दो राय नहीं कि परिसीमन का मुद्दा केवल सीटों के बंटवारे का नहीं, बल्कि देश की एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों की परीक्षा भी है। इसे क्षेत्रीय अस्मिता की लड़ाई बनाने की बजाय राष्ट्रीय हित में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना ही समय की मांग है।

बैटल ऑफ बंगाल में भाजपा और ममता की हर स्तर की लड़ाई

पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव, भारत के अन्य राज्यों के चुनावों की तरह नहीं बल्कि यह 1757 की प्लासी की लड़ाई की तरह है जब मुट्ठी भर क्लाइव की ब्रिटिश फौज ने तीन लाख की बंगाल के नबाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था और मीर जाफर को बंगाल का नबाब बना दिया था। वर्तमान विधानसभा चुनाव,जो कई आयामों, स्तरों, उद्देश्यों,के लिए शाम दाम, दंड से लड़ी जा रही है। पूरा राज्य बंगाल मय समाचार पत्रों, दृश्य मीडिया के दो फाड़ हो गया है। एक भाग भाजपा के साथ है तो दूसरा तृणमूल कांग्रेस के साथ है। वाकी सीपीएम, कांग्रेस दूसरे दल, केवल औपचारिक भूमिका में है। जहां तृणमूल कांग्रेस ने एस आई आर का मुद्दा उठाया है वही भाजपा 15 साल की भ्रष्टाचार, हिंसा, घुसपैठ को मुख्य मुद्दा बना रही है। 294 सदस्यीय विधानसभा चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होने है ।लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी समझमे आ गया है कि यह चुनाव पूरे देश से भिन्न है। बस इतना समझ लो कि भाजपा की भवानीपुर की रैली में बैंड बजा रहे दल की भी उसी रात तृणमूल के लठैत से मार मार खूनी खेल खेला। यह एक बानगी है और यह उस पार्टी के खिलाफ हो रहा है जो देश पर शासन कर रही है।

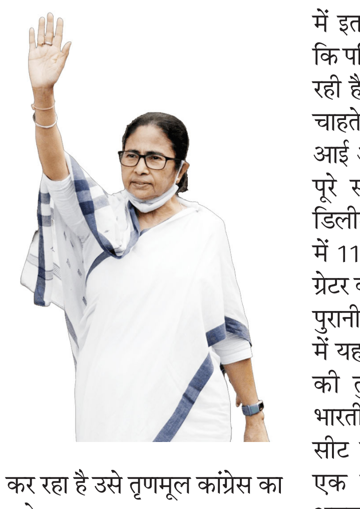

पोस्टर वाला, टांगें वाला, माइक वाला जो भाजपा के काम कर रहा है उसे तृणमूल कांग्रेस का कोप का भाजन बनाना पड़ेगा ।बंगाल का विधानसभा चुनाव इतना बोझिल है कि सर्वेक्षक भी हड़प्रभ है क्योंकि कोई भी मतदाता खुल कर अंकित नहीं कर रहा है ।टाइम्स ऑफ इंडिया के शीतल पाल सिंह कहते हैं कि असम, केरल, पांडिचेरी की तरह मतदाता पश्चिमी बंगाल में बोल नहीं रहा है क्योंकि उसे अज्ञात भय है। संदीप घोषाल वीरभूमि में कपड़ा व्यापारी है लेकिन चुनाव की बात करने ही तैयार नहीं बस यह कहते हैं कि दीदी ही आएगा। तृणमूल सरकार ने लोगों को अपनी चाल में ढाल दिया है।

भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई में सुबेदु अधिकारी को आगे कर चुनाव मैदान में है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिलीगुड़ी सभा कर रहे हैं और उनकी सभा में इतनी भीड़ है जो बता रही है कि पश्चिमी बंगाल में ज्वाला भभक रही है। लेकिन लोग बोलना नहीं चाहते हैं। ममता बनर्जी ने एस आई आर को मुद्दा बनाया है और पूरे सूबे से 90 लाख मतदाता डिलीट कर दिया है। कोलकाता में 11 विधानसभा क्षेत्र है जबकि ग्रेटर कोलकाता से या कहे अंग्रेजी पुरानी स्टेट में 107 सीट है 2021 में यहां पर 90 सीट ममता बनर्जी की तुड़मूल ने जीती थी और भारतीय जनता पार्टी को मात्र 15 सीट मिली थी सीपीएम कांग्रेस एक एक सीट पर जीती थी। अबकी बार भाजपा इस क्षेत्र से कुछ अच्छा स्कोर कर ना चाहती है। मालदा वीरभूमि, मेदिनीपुर, बांकुरा, चौबीस परगना, सहित अनेक जगह पर तुड़मूल, भाजपा में गजब की टक्कर है। आजादी के बाद पश्चिमी बंगाल में विधान चंद्र राय कांग्रेस के दिग्गज नेता थे उन्होंने आजादी के आंदोलन बहुत ही सराहनीय काम किया ।1977 तक कांग्रेस ही बंगाल की सत्ता में थी सिद्धार्थ शंकर राय मुख्यमंत्री रहे। आपातकाल के बाद हुए चुनावों में सीपीएम यानी लेफ्ट पार्टियों का समावेश हुआ और वे विधानसभा चुनाव में बहुमत लाने में सफल हुए।ज्योति बसु 27 वर्ष यानि 2000 तक मुख्यमंत्री रहे उनके बाद सीपीएम की विरासत बुद्धदेव भट्टाचार्य के हाथों में आई 2011 तक 10 वर्ष वह मुख्यमंत्री रहे।

मुंह की बदबू से परेशान हैं? इन तरीकों से करें दूर

मुंह की बदबू एक आम समस्या है, जिससे हर कोई कभी न कभी जूझता है। यह समस्या न केवल आत्मविश्वास को कम करती है, बल्कि सामाजिक जीवन में भी रुकावट डाल सकती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी टिप्स देंगे, जिनसे आप अपने मुंह की बदबू को दूर कर सकते हैं और ताजगी महसूस कर सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर आप अपने मुंह की देखभाल कर सकते हैं।

रोजाना दो बार ब्रश करना बहुत जरूरी है। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले ब्रश करें ताकि आपके दांत साफ रहें और कीटाणु न पनप सकें। सही तरीके से ब्रश करने से मुंह की बदबू भी दूर होती है। इसके लिए नरम बालों वाले ब्रश का उपयोग करें और फ्लोराइड वाला पेस्ट इस्तेमाल करें। ब्रश करते समय हल्के हाथों से दांतों के हर कोने को अच्छे से साफ करें। जीभ पर भी कीटाणु जमा होते हैं, जो मुंह की बदबू का कारण बन सकते हैं। इसलिए रोजाना ब्रश करने के साथ-साथ अपनी जीभ को भी साफ करें। इसके लिए आप जीभ साफ करने वाले उपकरण का उपयोग कर सकते हैं या फिर नरम ब्रश से हल्के हाथों से रगड़ सकते हैं। जीभ को साफ रखने से आपके मुंह की ताजगी बनी रहती है और आप बेझिझक बात कर सकते हैं बिना किसी चिंता के।

दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। इससे आपके शरीर में नमी बनी रहती है और लार बनने में मदद मिलती है, जो कीटाणु को खत्म करने में सहायक होती है। इसके अलावा पानी पीने से आपके गले और मुंह की सफाई होती रहती है। अगर आप नियमित रूप से पानी पीते हैं तो मुंह की बदबू की समस्या कम हो जाती है और आपका मुंह ताजा बना रहता है। बिना चीनी वाली च्युइंग गम चबाने से भी मुंह की बदबू दूर होती है।

आखिरकार सुनी गई आधी आबादी की आवाज़

भारत की महिलाएँ सदैव महान कार्यों में सक्षम रही हैं। वैदिक काल में गार्गी और मैत्रेयी ने बड़े-बड़े दार्शनिकों को निरुत्तर कर दिया था। पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर ने जिस न्यायपूर्ण तरीके से अपने राज्य का शासन चलाया, उसकी बराबरी उनके समकालीन शासक नहीं कर सके। रानी लक्ष्मीबाई साहस की एक अमर मिसाल बन गईं। फिर भी, स्वतंत्र भारत—जो समानता के सिद्धांत पर आधारित एक संवैधानिक गणराज्य है ने इन महान महिलाओं की उत्तराधिकारियों को अपनी विधायिकाओं में शायद ही कोई जगह दी। पहली लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या मात्र 4.4 प्रतिशत थी। सात दशक बाद, 17वीं लोकसभा में भी यह आंकड़ा बढ़कर केवल 14.4 प्रतिशत तक ही पहुँच पाया। व्यक्तिगत प्रतिभा ने तो अपनी जगह बना ली थी, लेकिन व्यवस्थागत बदलाव अभी भी नहीं आया था। असल में, महिलाएं अपने ही लोकतंत्र में एक तरह से मेहमान बनकर ही रह गईं।

हमारे संविधान ने पहले ही दिन से यह स्वीकार किया था कि जब सदियों से ढांचागत विसंगतियां जड़ जमाए बैठी हों, तो केवल औपचारिक समानता पर्याप्त नहीं होती। संरक्षणात्मक भेदभाव के सिद्धांत के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और बाद में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गईं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था सफल रही है- 24 मार्च 2026 तक, निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों में से लगभग 49.75 प्रतिशत महिलाएँ हैं। जिन जगहों पर महिलाएँ शासन करती हैं, वहाँ पानी की आपूर्ति सुचारू होती है, साफ़-सफ़ाई की स्थिति बेहतर होती है और लड़कियाँ स्कूल जाना जारी रखती हैं। इसके बावजूद, संसद में भी इसी सिद्धांत को लागू करने के उद्देश्य से जो विधेयक पेश किए गए थे, वे राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में दशकों तक बार-बार निष्प्रभावी होते रहे।

वह अधूरी कड़ी 19 सितंबर 2023 को पूरी हुई। भारत के नए संसद भवन में आयोजित कामकाज के पहले ही सत्र में, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद के दोनों सदनों में, प्रत्येक राजनीतिक दल के सर्वसम्मत समर्थन से पारित किया गया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पेश करते हुए दोनों सदनों को बताया–यह कानून केवल एक कानून नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक भारतीय महिला की शक्ति, त्याग और सामर्थ्य के प्रति एक श्रद्धांजलि है। यह अधिनियम लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करता है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए उप-कोटा भी शामिल है। नए संसद भवन का यह पहला अधिनियम होना अपने आप में एक घोषणा थी- अमृत काल के लोकतंत्र की संरचना पूरे भारत के लिए और सभी की भागीदारी के साथ निर्मित की जाएगी।

इस अधिनियम में बदलाव लाने की अपार क्षमता है, क्योंकि इसके लागू होने से संसद में महिला सदस्यों की संख्या में भारी वृद्धि होगी। महिला विधायक निरंतर स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता देती हैं—ये वही क्षेत्र हैं, जहाँ भारत में लैंगिक असमानता सबसे अधिक है। एक ऐसी संसद, जिसमें एक-तिहाई सदस्य महिलाएँ होंगी, वह अलग तरह के प्रश्न पूछेगी और अलग तरह के विचार सुनेगी।

नारी-आरक्षण : नये भारत का आधार एवं संभावनाओं का शिखर

नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भारत की राजनीति और समाज में जो नई चेतना उभरकर सामने आई है, वह केवल एक विधायी परिवर्तन का संकेत नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक रूपांतरण एवं नये भारत-निर्माण की संभावनाओं की प्रस्तावना है। निश्चित तौर पर भारत अब अपने विकास की धुरी में महिलाओं की सक्रिय और निर्णायक भागीदारी को अनिवार्य मानने लगा है। दशकों से लंबित महिला आरक्षण का मुद्दा केवल संसद के गलियारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह भारतीय समाज की उस अंतर्धारा से जुड़ा रहा है, जिसमें बराबरी, सम्मान और अवसर की मांग निरंतर उठती रही है। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह सही कहा कि यह इस सदी के महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। पहले यह अधिनियम नई जनगणना के बाद लागू होना था, पर उसमें देरी के चलते सरकार ने इसे 2011 की जनगणना के आधार पर लागू करने का निर्णय किया। इस पर विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई है, पर इस आपत्ति को महत्व देने से अगले लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण लागू करना संभव नहीं होगा, क्योंकि ताजा जनगणना के आंकड़ों के आधार पर बनने वाले परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आने में समय लगता और तब तक 2029 के आम चुनाव हो जाते। इसी कारण इस अधिनियम में संशोधन करने हेतु संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया है। चूंकि यह सत्र विधानसभा चुनावों के बीच बुलाया जा रहा है, इसलिए भी कई विपक्षी दलों को यह कांटों की तरह चुभन दे रहा है ।राजनीति

भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी का इतिहास विरोधाभासों से भरा रहा है। एक ओर देश ने इंदिरा गांधी जैसी सशक्त महिला नेतृत्व को देखा, वहीं दूसरी ओर संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या लंबे समय तक सीमित बनी रही। वर्तमान में लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी लगभग 15 प्रतिशत के आसपास है, जो यह बताती है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के स्तर पर अभी भी एक बड़ा अंतर विद्यमान है। इस संदर्भ में महिला आरक्षण अधिनियम उस अंतर को पाटने का एक संगठित और संरचनात्मक प्रयास है। महत्वपूर्ण यह भी है कि इस अधिनियम को लागू करने के संदर्भ में जनगणना और परिसीमन को लेकर जो विवाद सामने आया है, वह भारतीय लोकतंत्र की जटिलताओं को भी उजागर करता है। सरकार द्वारा 2011 की जनगणना के आधार पर इसे लागू करने का निर्णय एक व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, क्योंकि नई जनगणना और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया में होने वाली देरी महिला आरक्षण को वर्षों तक टाल सकती थी। विपक्ष की आशंकाएं अपनी जगह पर हैं, परंतु अभी तक उनके समर्थन में ठोस तथ्य सामने नहीं आए हैं।

भारतीय राजनीति में किसी भी बड़े निर्णय को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की परंपरा रही है और महिला आरक्षण भी इससे अछूता नहीं है। विपक्ष द्वारा यह आरोप लगाना कि सरकार इस पहल के माध्यम से राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा है। किन्तु यह भी उतना ही सत्य है कि लोकतंत्र में लिए जाने वाले अधिकांश निर्णयों के पीछे राजनीतिक गणित काम करता है। प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि निर्णय के पीछे राजनीतिक लाभ है या नहीं, बल्कि यह होना चाहिए कि उसका प्रभाव समाज पर कितना सकारात्मक पड़ता है। यदि महिला आरक्षण से महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है और नीति निर्माण में उनका दृष्टिकोण शामिल होता है, तो यह संपूर्ण समाज के लिए लाभकारी होगा। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका में एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला है। महिलाएं अब केवल मतदाता नहीं रहीं, बल्कि वे एक निर्णायक मतदाता वर्ग के रूप में उभरी हैं। 2019 के आम चुनावों में महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुषों के लगभग बराबर रही और कई राज्यों में उन्होंने पुरुषों से अधिक मतदान किया। यह परिवर्तन केवल संख्या का नहीं, बल्कि चेतना का संकेत है। महिलाएं अब अपने अधिकारों और हितों के प्रति अधिक सजग हो रही हैं और राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं।

सरकारी योजनाओं ने भी इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से रसोई गैस की उपलब्धता, जनधन योजना के तहत बैंकिंग सुविधा, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण और मातृत्व लाभ योजनाओं ने महिलाओं के जीवन में प्रत्यक्ष सुधार किया है। इन योजनाओं का प्रभाव केवल आर्थिक या भौतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक भी रहा है, जिससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे सार्वजनिक जीवन में अधिक सक्रिय हुई हैं। डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों को इस संदर्भ में विशेष रूप से स्मरण किया जाना चाहिए। उन्होंने भारतीय संविधान के माध्यम से समानता और न्याय के सिद्धांतों को स्थापित करते हुए महिलाओं को समान अधिकार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। उनका यह विश्वास था कि किसी भी समाज की प्रगति का आकलन वहां की महिलाओं की स्थिति से किया जा सकता है। आज जब महिला आरक्षण की बात हो रही है, तो यह उसी विचारधारा का विस्तार प्रतीत होता है, जिसमें महिलाओं को केवल संरक्षण नहीं, बल्कि सशक्तिकरण का अवसर प्रदान किया जाता है।

हालांकि यह भी समझना आवश्यक है कि महिला आरक्षण अपने आप में कोई अंतिम समाधान नहीं है। यह एक आवश्यक कदम है, परंतु पर्याप्त नहीं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ने से महिलाओं की आवाज अवश्य मजबूत होगी, परंतु सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर पर समानता स्थापित करने के लिए और भी प्रयास करने होंगे। आज भी भारत में महिला श्रम भागीदारी दर लगभग 25 प्रतिशत के आसपास है, जो वैश्विक औसत से काफी कम है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई है, परंतु उच्च शिक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाने की आवश्यकता है। महिला आरक्षण के क्रियान्वयन के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। यह आशंका व्यक्त की जाती रही है कि कई स्थानों पर महिलाएं केवल नाममात्र की प्रतिनिधि बनकर रह जाएंगी और वास्तविक निर्णय उनके पुरुष परिजन लेंगे। पंचायत स्तर पर इस तरह के उदाहरण देखने को मिले हैं, परंतु समय के साथ महिलाओं ने इस स्थिति को बदला भी है और अपने अधिकारों को स्वयं संभालने की क्षमता विकसित की है। इसी प्रकार राजनीतिक प्रशिक्षण और नेतृत्व विकास की आवश्यकता भी महत्वपूर्ण है, ताकि महिलाएं केवल प्रतिनिधि न होकर प्रभावी नीति निर्माता बन सकें। इसके साथ ही राजनीतिक दलों की आंतरिक संरचना में भी परिवर्तन आवश्यक है। यदि दल अपने संगठनात्मक ढांचे में महिलाओं को पर्याप्त स्थान नहीं देंगे, तो केवल आरक्षण के माध्यम से वास्तविक सशक्तिकरण संभव नहीं होगा। दलों को चाहिए कि वे महिलाओं को नेतृत्व के अवसर प्रदान करें, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित करें और उनके लिए अनुकूल वातावरण तैयार करें।

नया भारत जिस विकसित राष्ट्र की कल्पना कर रहा है, उसमें नारी शक्ति की भूमिका केंद्रीय है। आज भारतीय महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। विज्ञान, तकनीक, खेल, शिक्षा, प्रशासन और उद्यमिता-हर क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां यह प्रमाणित करती हैं कि अवसर मिलने पर वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकती हैं। इसरो की महिला वैज्ञानिकों की सफलता, ओलंपिक में पदक जीतने वाली खिलाड़ियों का प्रदर्शन, और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण के उदाहरण इस परिवर्तन के सशक्त प्रमाण हैं। इस अधिनियम के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि विकास का कोई भी मॉडल तब तक पूर्ण नहीं हो सकता, जब तक उसमें आधी आबादी की समान भागीदारी सुनिश्चित न हो। हालांकि इसके क्रियान्वयन में राजनीतिक मतभेद और व्यावहारिक चुनौतियां सामने आती रहेंगी, परंतु इसकी मूल भावना पर प्रश्नचिह्न नहीं लगाया जा सकता। आवश्यकता इस बात की है कि इसे एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन के अवसर के रूप में देखा जाए। यदि सरकार, विपक्ष और समाज मिलकर इस दिशा में कार्य करते हैं, तो यह अधिनियम न केवल महिलाओं के लिए, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए एक नई दिशा निर्धारित कर सकता है। यही वह मार्ग है, जिस पर चलते हुए भारत एक सशक्त, समावेशी और विकसित राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान को और अधिक मजबूत कर सकता है।

थलपति संग अफेयर की खबरों के बीच तृषा कृष्णन के घर को बम से उड़ाने की मिली धमकी, एक्शन मोड में पुलिस

साउथ सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस तृषा कृष्णन इन दिनों न केवल अपनी फिल्मों, बल्कि अपनी निजी जिंदगी और सुरक्षा को लेकर भी सुर्खियों में बनी हुई हैं। थलपति विजय के साथ उनके कथित रिश्तों की अफवाहों के बीच, अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने उनके फैंस और फिल्म जगत को चिंता में डाल दिया है। हाल ही में चेन्नई स्थित उनके आवास को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया।यह घटना सोमवार सुबह की है, जब लगभग 9:30 बजे तमिलनाडु पुलिस के डीजीपी कंट्रोल रूम को एक गुमनाम ईमेल प्राप्त हुआ। इस ईमेल में दावा किया गया था कि एक्ट्रेस तृषा कृष्णन के चेन्नई स्थित घर में भारी मात्रा में विस्फोटक छिपाकर रखा गया है और जल्द ही वहां धमाका होने वाला है। इस तरह की गंभीर सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन तुरंत एक्शन मोड में आ गया। बिना किसी देरी के, पुलिस की एक बड़ी टीम के साथ बम निरोधक दस्ता एक्ट्रेस के आवास पर पहुंच गया।धमकी मिलते ही सुरक्षा बलों ने तृषा के घर के चारों ओर घेराबंदी कर दी। बम निरोधक दस्ते और स्निफर डॉग्स की मदद से घर के कोने-कोने की गहन तलाशी ली गई। कई घंटों तक चली इस सघन जांच के बाद, अधिकारियों ने राहत की सांस ली जब घर के अंदर कोई भी विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। जांच के उपरांत पुलिस ने आधिकारिक तौर पर स्पष्ट किया कि यह ईमेल पूरी तरह से एक %हॉक्स% यानी फर्जी धमकी थी, जिसका उद्देश्य केवल दहशत फैलाना था।दोबारा दोहराई गई डराने वाली घटना

हैरानी की बात यह है कि तृषा के साथ इस तरह की घटना पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले 2 अक्टूबर 2025 की रात को भी उनके घर को लेकर ऐसी ही एक डरावनी धमकी मिली थी। उस समय भी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने रात भर तलाशी अभियान चलाया था, लेकिन अंत में वह भी एक अफवाह ही साबित हुई थी। बार-बार मिल रही इन फर्जी धमकियों ने न केवल एक्ट्रेस की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी अतिरिक्त दबाव बना दिया है।

एक-दूसरे से भिड़े प्रियंका और अभिषेक

टीवी की नागिन यानी प्रियंका चाहर चौधरी और अभिषेक मल्लान के बीच सबकुछ ठीक-ठाक नहीं है. हाल ही में दोनों ऑनलाइन एक-दूसरे से भिड़ते हुए नजर आए.जल्द ही दोनों एक रिएलिटी शो में नजर आएंगे.रिएलिटी शो बैटलग्राउंड को होस्ट करने के लिए अभिषेक मल्हान पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार प्रियंका चाहर चौधरी भी इस शो का हिस्सा बनने वाली हैं.वो भी अभिषेक के संग मिलकर इस शो को होस्ट करेंगी. इसी बीच, अभिषेक को प्रियंका ने ऑनलाइन रोस्ट कर दिया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया.

पोस्ट शेयर कर बोले यूट्यूबर-इच्छाधारी नागिन जी..

अब प्रियंका के रोस्ट का अभिषेक मल्हान ने अपने अंदाज में जवाब दिया है. अभिषेक ने पोस्ट शेयर कर लिखा,प्रियंका जी कह रही हैं कि रोस्ट करना आता होगा तो करेगा.मैंने कहा,इछाधारी नागिन जी, ये इछा भी आपकी पूरी कर देंगे, आप बैटलग्राउंड में मिलिए हमें.

बता दें बैटलग्राउंड सीजन 2 में अभिषेक मल्हान और राहुल चौधरी के साथ प्रियंका चाहर चौधरी को भी मेंटर के तौर पर देखा जाएगा.अभिषेक मल्हान के बारे में बता दें उन्हें बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में कंटेस्टेंट के तौर पर देखा गया था, इस सीजन में वो रनर-अप बने थे.

वहीं, प्रियंका चाहर चौधरी बिग बॉस 16 का हिस्सा बनी थीं और टॉप थ्री में शामिल हुई थीं.अभिषेक और प्रियंका के बीच चल रहे इस नोकझोंक ने दर्शकों के अंदर बैटलग्राउंड सीजन 2 को लेकर और भी यादा एक्साइटमेंट बढ़ा दी है.दर्शक इस रिएलिटी शो में दोनों की केमिस्ट्री को देखने के लिए काफी बेताब नजर आ रहे हैं.

आपको बता दें अभिषेक मल्हान एक पॉपुलर यूट्यूबर और इन्फलुएंसर हैं. 2019 में अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया था, तबसे लेकर अब तक वो दर्शकों को खूब एंटरटेन करते हुए नजर आ रहे हैं.अभिषेक मल्हान के इंस्टाग्राम पर 12.5 मिलियन फॉलोवर्स हैं, जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं.

यूट्यूब से पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद अभिषेक मल्हान ने ओटीटी की तरफ रुख किया. उन्हें अब तक कई म्यूजिक वीडियोज में भी देखा जा चुका है. जल्द ही वो दिशा पाटनी की बहन खूशबू पाटनी के संग एक और रिएलिटी शो को होस्ट करते हुए दिखाई देंगे।

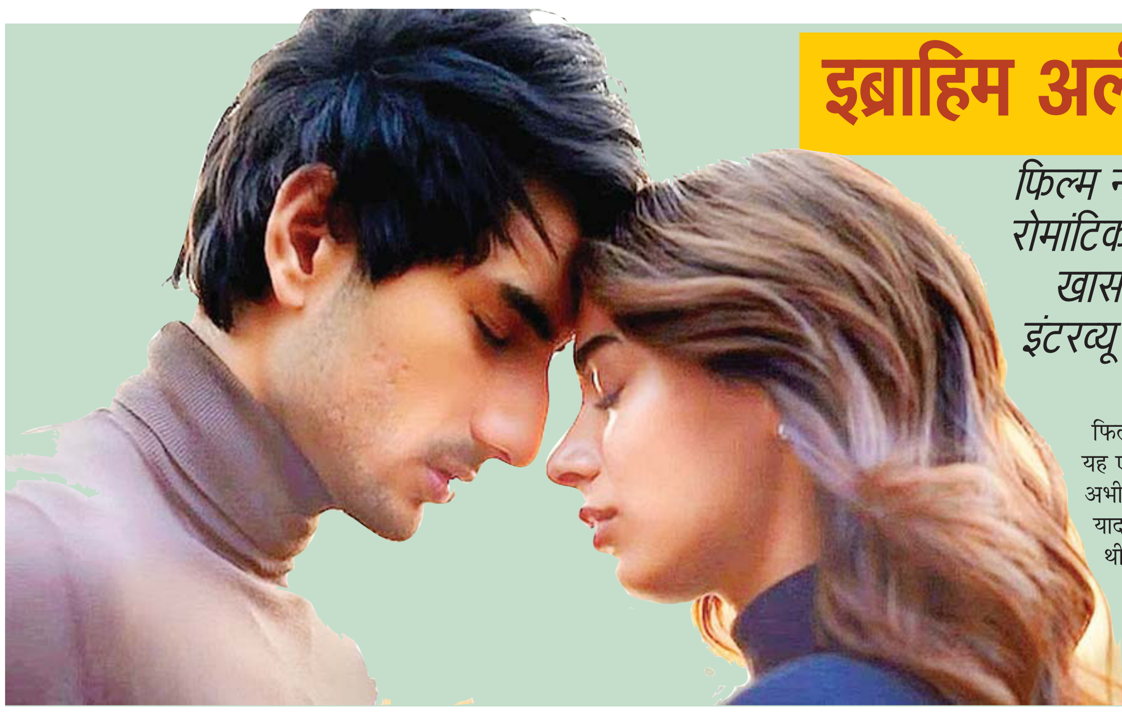

इब्राहिम अली ने सोशल मीडिया को बताया नफरत भरी दुनिया

फिल्म नादानियां से सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म में खुशी कपूर भी थीं। भले ही फिल्म ने काफी चर्चा बटोरी, लेकिन यह कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। और सोशल मीडिया पर इसे मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिलीं। एक नए इंटरव्यू में, इब्राहिम ने आलोचना के बारे में खुलकर बात की और कहा कि सोशल मीडिया एक नफरत भरी दुनिया है। यह बहुत कुछ तोड़-मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करती है।

फिल्मफेयर के साथ हाल ही में एक इंटरव्यू में, इब्राहिम अली खान ने नादानियां पर अपनी बात रखी है। अब्राहिम ने कहा कि नादानियां कोई भव्य फिल्म नहीं थी। यह एक प्यारी, मजेदार रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म थी जिसका आनंद आपको शुक्रवार की रात बिस्तर पर आराम करते हुए लेना चाहिए। उन्होंने कहा सोशल मीडिया अभी एक नफरत भरी दुनिया है। लोगों ने इसे बहुत यादा तोड़-मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की है। एक अभिनेता के तौर पर मैंने जो किया है, मुझे उससे कहीं यादा करना है। मैं जो था, उससे खुश हूं। मैंने एक अछी फिल्म बनाई। मुझे आलोचनाएं मिली, लेकिन मुझे काम करने में मजा आया। मेरे हिसाब से यह अछी फिल्म थी। खुद को पांच में से 3.5 स्टार देते हुए इब्राहिम ने कहा बहुत यादा मत उड़ो, लेकिन खुद को कम भी मत समझो। नादानियां को मिली-जुली प्रतिक्रियाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए, इब्राहिम ने कहा यादातर प्रतिक्रियाएं खराब हैं क्योंकि सोशल मीडिया ऐसे ही काम करता है। उन्होंने कहा, मैं फिल्म उद्योग से मिली प्रतिक्रिया से खुश हूं।टाइम्स नाउ से हाल ही में हुई बातचीत के दौरान शर्मिला टैगोर ने अपने पोते की फिल्म नादानियां के बारे में बात की। अभिनेत्री ने कहा कि भले ही फिल्म अछी नहीं थी, लेकिन इब्राहिम हैंडसम लग रहे थे। टैगोर ने कहा, ये बातें सबके सामने नहीं कही जानी चाहिए, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो फिल्म अछी नहीं थी। आखिरकार, फिल्म अछी होनी ही चाहिए।

सीबीएसई 10वीं परिणाम में कैम्ब्रिज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बक्सर का शानदार जलवा, 98.2% अंक के साथ अन्वी और आशीष बने संयुक्त टॉपर

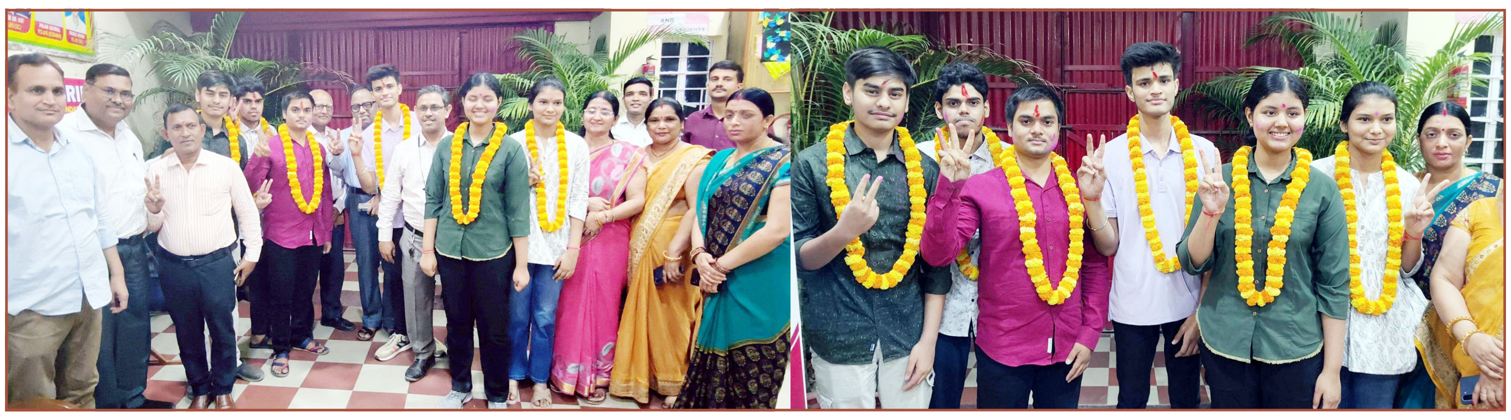

बक्सर (संवाददाता)। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित होते ही बक्सर स्थित कैम्ब्रिज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में खुशी की लहर दौड़ गई। जैसे ही परिणाम सामने आए, विद्यालय परिसर में जश्न का माहौल बन गया। छात्र-छात्राएं, शिक्षक और अभिभावक सभी इस ऐतिहासिक सफलता से बेहद उत्साहित नजर आए।

इस वर्ष विद्यालय के छात्रों ने न केवल शानदार प्रदर्शन किया, बल्कि जिले में भी अपनी अलग पहचान बनाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुमारी अन्वी और आशीष कुमार गुप्ता ने 98.2 प्रतिशत अंक हासिल कर संयुक्त रूप से विद्यालय टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया। दोनों छात्रों की इस उपलब्धि ने विद्यालय का नाम ऊंचा कर दिया है और अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। वहीं आदर्श कुमार ठाकुर ने 96 प्रतिशत अंक लाकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। तीसरे स्थान पर खुशी कुमारी और आयुष गुप्ता रहे, जिन्होंने 95.4 प्रतिशत अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इन छात्रों की सफलता ने यह साबित कर दिया कि मेहनत, अनुशासन और सही मार्गदर्शन से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

विद्यालय के अन्य मेधावी छात्रों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। किशन कुमार राय और आदित्य तिवारी ने 94.8 प्रतिशत अंक प्राप्त किए, जबकि अनुजा रिमझिम ने 94.2 प्रतिशत और सत्यम चौबे ने 94 प्रतिशत अंक हासिल किए। इसके अलावा आराध्य सिंह ने 92.4 प्रतिशत अंक प्राप्त किए, वहीं हिबा कुल्सुम और शानवी गुप्ता ने 92 प्रतिशत अंक लाकर अपनी उत्कृष्टता का परिचय दिया। अनुष्का प्रसाद और भव्य श्रीवास्तव ने 91.8 प्रतिशत अंक हासिल किए, अयुष आनंद ने 91.6 प्रतिशत, वंशिका अग्रवाल और अभय उपाध्याय ने 91.4 प्रतिशत, जबकि समीर अहमद और अश्विक प्रियम ने 91.2 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। इन सभी छात्रों की उपलब्धियां इस बात का प्रमाण हैं कि विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समर्पित शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध है।

विषयवार प्रदर्शन की बात करें तो छात्रों ने यहां भी उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया। संस्कृत विषय में कुमारी अन्वी, आशीष कुमार गुप्ता, भव्य श्रीवास्तव और किशन कुमार राय ने 100 में 100 अंक प्राप्त कर विशेष उपलब्धि दर्ज की। वहीं गणित विषय में आशीष कुमार गुप्ता ने पूर्णांक प्राप्त कर अपनी असाधारण क्षमता का परिचय दिया। अन्य विषयों में भी अधिकांश छात्रों ने उच्च अंक हासिल किए, जो उनकी मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम है।

इस अभूतपूर्व सफलता पर विद्यालय में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। छात्र-छात्राएं एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। शिक्षकों और अभिभावकों ने भी बच्चों की इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया। विद्यालय के निदेशक डॉ. मोहन चौबे, एक्जीक्यूटिव प्राचार्य बी. एस. राव, प्राचार्य एम. के. चौबे, उप-प्राचार्य कृष्णकांत ओझा और धर्मवीर दूबे सहित सभी शिक्षकों ने छात्रों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि यह सफलता छात्रों की कठिन मेहनत, शिक्षकों के समर्पण और अभिभावकों के सहयोग का संयुक्त परिणाम है। साथ ही यह भी बताया गया कि विद्यालय भविष्य में भी छात्रों को बेहतर शिक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा।

इस शानदार परिणाम ने न केवल विद्यालय, बल्कि पूरे बक्सर जिले को गौरवान्वित किया है। छात्रों की इस ऐतिहासिक सफलता से विद्यालय परिसर में हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है और आने वाले वर्षों के लिए एक नया मानक स्थापित हुआ है।

बक्सर व्यवहार न्यायालय में लिफ्ट सेवा का शुभारंभ, दिव्यांग वकीलों व पक्षकारों को मिली बड़ी राहत

बक्सर (संवाददाता)। बक्सर के व्यवहार न्यायालय परिसर में बुधवार को एक महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित सुविधा का शुभारंभ किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश काजल झांब ने विधिवत फीता काटकर न्यायालय भवन में स्थापित नई लिफ्ट सेवा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर न्यायिक एवं अधिवक्ता समुदाय के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे और इस पहल की सराहना की।

लंबे समय से न्यायालय परिसर में लिफ्ट की सुविधा नहीं होने के कारण वकीलों, पक्षकारों और आम लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। खासकर दिव्यांग वकीलों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं और बुजुर्ग पक्षकारों के लिए ऊपरी मंजिलों तक पहुंचना बेहद चुनौतीपूर्ण होता था। अब लिफ्ट सेवा शुरू होने से इन सभी वर्गों को बड़ी राहत मिलेगी और न्यायालय तक उनकी पहुंच अधिक सुगम हो सकेगी। उद्घाटन समारोह के दौरान बार संघ के अध्यक्ष भवन ओझा, प्रधान न्यायाधीश मनोज कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता महावीर त्रिवेदी एवं मोहम्मद अजीज अब्बास सहित कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। सभी ने इस सुविधा को न्यायिक व्यवस्था में एक सकारात्मक और आवश्यक बदलाव बताया।

इस अवसर पर न्यायिक पदाधिकारियों में सुनील कुमार सिंह, अमित कुमार शर्मा, कमल कुमार, मानस कुमार, सुमत कुमार सिंह, सुधांशु पांडे, भोला सिंह, महेश्वर पांडे, नेहा दयाल, सचिन विदेशी, बिंदेश्वरी पांडे, आनंद मोहन उपाध्याय, प्रभुनाथ सिंह, सुरेश सिंह, गणपति मंडल, सुरेश श्रीवास्तव, रमाकांत तिवारी, बिनोद मिश्रा, रंजना कुमारी, नीरज कुमार और संतोष दुबे सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे।

कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि यह सुविधा न केवल न्यायालय परिसर में आने-जाने को आसान बनाएगी, बल्कि न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी और संवेदनशील बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे दिव्यांगजनों और बुजुर्गों को अब न्यायालय तक पहुंचने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। लिफ्ट सेवा शुरू होने के बाद न्यायालय परिसर में उत्साह का माहौल देखा गया। अधिवक्ताओं और आम नागरिकों ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे जनहित में उठाया गया सराहनीय कदम बताया। यह सुविधा न्यायिक प्रणाली को अधिक आधुनिक, सुलभ और जनोन्मुख बनाने में सहायक सिद्ध होगी। इस प्रकार बक्सर व्यवहार न्यायालय में लिफ्ट सेवा का शुभारंभ एक ऐतिहासिक पहल के रूप में देखा जा रहा है, जो आने वाले समय में न्यायालय परिसर में आने वाले सभी लोगों के लिए बड़ी सहूलियत लेकर आएगा।

चोरी के शक में युवक को पेड़ से उल्टा लटकाकर पीटा

बक्सर (संवाददाता)। बिहार के बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां चोरी के शक में ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़कर पेड़ से उल्टा लटका दिया और लाठी-डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है।

बताया जा रहा है कि घटना रविवार देर रात की है। ग्रामीणों के मुताबिक, रात करीब तीन बजे एक संदिग्ध युवक गांव में घुसा था। आहट सुनकर लोग जाग गए और उसे पकड़ लिया। इसके बाद भीड़ ने कानून अपने हाथ में लेते हुए युवक को रस्सी से बांधकर पेड़ से उल्टा लटका दिया और उसकी जमकर पिटाई की। मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो अब इंटरनेट पर वायरल है। पीड़ित युवक की पहचान बेटानी यादव के रूप में हुई है, जो उसी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को भीड़ से छुड़ाकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज हुआ।

मामले में उस समय नया मोड़ आया जब युवक के परिजनों ने चोरी के आरोपों को नकार दिया। उनका कहना है कि यह घटना पुरानी रंजिश का परिणाम है और उनके बेटे को साजिश के तहत झूठे आरोप में फंसाकर पीटा गया। परिजनों ने पुलिस से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मुफस्सिल थाना अध्यक्ष शंभू भगत ने बताया कि युवक ने किसी के खिलाफ लिखित शिकायत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद प्राथमिक उपचार और पूछताछ के बाद उसे घर भेज दिया गया। फिलहाल, वायरल वीडियो और दोनों पक्षों के दावों के बीच सच्चाई क्या है, यह पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। यह घटना एक बार फिर भीड़ द्वारा कानून हाथ में लेने के खतरनाक और अमानवीय पहलू को उजागर करती है।

बिहार सेंट्रल स्कूल में मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान, प्रमाण पत्र और ट्रॉफी देकर बढ़ाया उत्साह

बक्सर (संवाददाता)।

बक्सर के बिहार सेंट्रल स्कूल में बुधवार को एक प्रेरणादायक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। वार्षिक परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर उत्साह, गर्व और खुशी के माहौल से भर गया।

विद्यालय प्रबंधन के सचिव सरोज सिंह ने कहा कि हर वर्ष बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करना विद्यालय की परंपरा है। यह दिन छात्रों के लिए खास होता है क्योंकि उन्हें अपनी मेहनत और लगन का प्रतिफल मिलता है। उन्होंने कहा कि ऐसे सम्मान से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे भविष्य में और बेहतर करने के लिए प्रेरित होते हैं। यह उपलब्धि केवल छात्रों की नहीं, बल्कि पूरे विद्यालय परिवार के लिए गर्व का विषय है। शिक्षकों के मार्गदर्शन और विद्यार्थियों की मेहनत का ही परिणाम है कि वे इस मुकाम तक पहुंचते हैं।

उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धी दौर के लिए तैयार करना और उनकी अध्ययन क्षमता को मजबूत बनाना है। सरोज सिंह ने जोर देते हुए कहा कि विद्यालय की असली सफलता तब होगी, जब अंतिम पंक्ति का छात्र भी आगे बढ़कर प्रथम स्थान हासिल करे। उन्होंने यह भी कहा कि विद्यार्थियों की सफलता केवल अंकों तक सीमित न होकर उनके आचरण और सामाजिक व्यवहार में भी दिखाई देनी चाहिए। समारोह में नर्सरी से कक्षा 9 तक के कई छात्रों को सम्मानित किया गया, जिनमें अविरल पांडे, सृष्टि श्रीवास्तव, अंशु, अपराजिता, अर्नव आनंद, ऋषभ यादव, प्रताप सिंह, अंकुश आनंद, वैष्णवी गुप्ता, नवनीत कुमार राय, विक्रांत सिंह,

कुमारी अर्चना, वैष्णवी कुमारी, अनामिका मिश्रा, सुमन वर्मा, राजनंदनी, किशन राज, नीरज दुबे और वरदान पांडे शामिल रहे। सम्मानित विद्यार्थियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि सफलता का मूल मंत्र स्वाध्याय, नियमित अभ्यास, धैर्य और अनुशासन है। कार्यक्रम ने यह संदेश दिया कि सही मार्गदर्शन, निरंतर मेहनत और आत्मविश्वास से हर छात्र सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है।

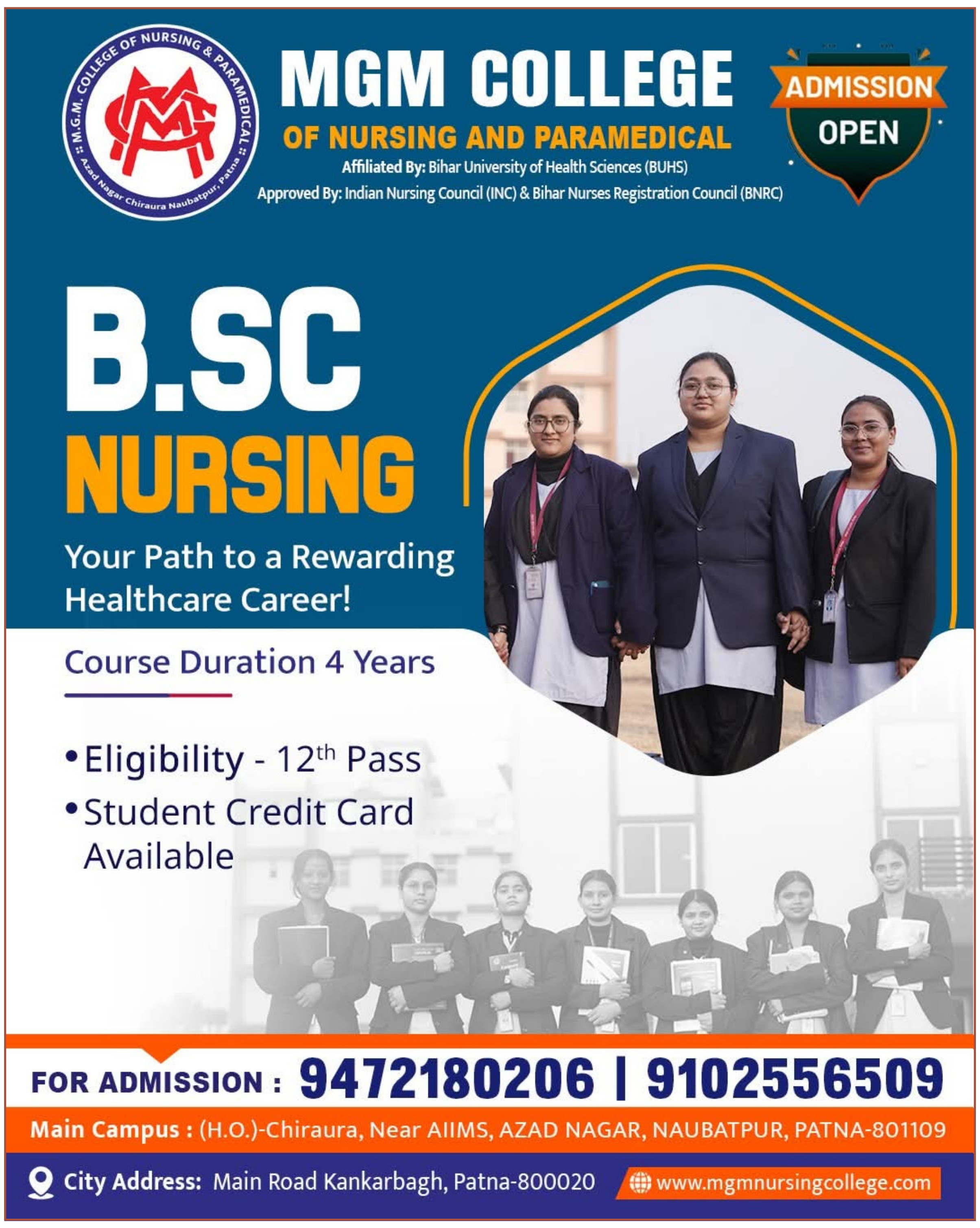

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक मतिउर्रहमान द्वारा अजीमाबाद प्रिंटर्स, आर. सी. एफ./105, ग्राउण्ड फ्लोर, बी. एच. कॉलोनी, भूतनाथ रोड, कंकड़बाग, पटना- 800026 बिहार से मुद्रित एवं अमला टोली, मेन रोड़, बक्सर -802101, बिहार से प्रकाशित, संपादक- मतिउर्रहमान, E-mail:- qalamlok@gmail.com, Regn. No. BIHHIN/2017/72480